RNI No. DELMUL/2012/47011

02 अगस्त, 2026 रविवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 122

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरिज के लिए फिट हुए जसप्रीत बुमराह 07

संक्षिप्त वार्ता

पप्पू यादव की निकाली शवयात्रा, सिर लाने वाले को 51 लाख देने का ऐलान

लखनऊ। लखनऊ में शनिवार को सनातन रक्षा संगठन ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव की शवयात्रा निकाली। यात्रा में संगठन के कार्यकर्ता अखिलेश यादव और राहुल गांधी का मुखौटा लगाए थे। प्रदर्शनकारी पप्पू यादव मुदार्बाद, राहुल गांधी-अखिलेश यादव मुदार्बाद के साथ राम नाम सत्य बोल रहे थे। गांधी प्रतिमा पर पहुंचने पर पप्पू यादव के शव रूपी पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान संगठन के लोगों ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। संगठन की तरफ से पप्पू यादव का सर लाने वाले को 51 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई।

देश में गंदगी फैलाते, विदेश में जाकर जेंटलमैन बन जाते: हाईकोर्ट की कड़ी फटकार

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश में स्वच्छता के प्रति लापरवाही बरतने और जगह-जगह कचरा फैलाने वालों को कड़ी फटकार लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी कर कहा कि ये लोग अपने देश में गंदगी फैलाते हैं, लेकिन विदेश जाते ही सुधर जाते हैं और जेंटलमैन होने का नाटक करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सवाल उठाया कि जब विदेश में तय जगह पर कचरा डाला जा सकता है, तब अपने देश में क्यों नहीं। अदालत ने कहा कि साफ-सफाई की जिम्मेदारी समाज की भी है और लोगों को कम से कम अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए।

मौसम ने दिखाया रौद्र रुप, सूरत में 24 घंटे में 24 इंच वर्षा

केरल में भूस्खलन से 3 की मौत, असम में बाढ़ से मृतकों की संख्या 82 पहुंची, 18 राज्यों में मौसम अलर्ट जारी

वेब वार्ता, नई दिल्ली

देश के कई हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। गुजरात, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड, असम और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को गुजरात और केरल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में ऑरेंज तथा बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड सहित 12 राज्यों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।

गुजरात में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सूरत में 24 घंटे के दौरान 24 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि राज्य के 12 अन्य क्षेत्रों में 10 इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड हुई। नवसारी के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है और पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। केरल में लगातार बारिश के चलते इडुक्की और कोट्टायम जिलों में भूस्खलन की अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के बीच राहत एवं बचाव कार्य जारी है। दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी के चलते स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार वर्षा के कारण एहतियातन केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते गंगा, घाघरा-सरयू सहित 10 नदियां उफान पर हैं और 71 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में जालोर और सिरोही के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा 18 अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन्फ्लूएंजा के मामले बढ़े

इस मानसून के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में एच1एन1 इन्फ्लूएंजा के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार तापमान में बदलाव के कारण वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मरीजों में गले में खराश, नाक बहना, सूखी खांसी और सिरदर्द जैसे लक्षण अधिक देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

अडाणी ने की 11 करोड़ की सहायता देने की घोषणा

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में दो और लोगों की मौत के बाद राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। प्रभावित लोगों की सहायता के लिए उद्योगपति गौतम अडाणी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

गुरुग्राम-जयपुर हाइवे आज से बैरियर-फ्री

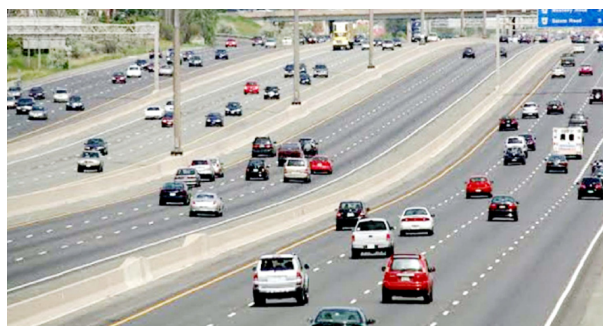

वेब वार्ता, नई दिल्ली

270 किमी का सफर बिना रुकावट करें : मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम होगा लागू

गुरुग्राम-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर अब सफर करना और सुगम और तेज होने वाला है। 1 अगस्त 2026 से महत्वपूर्ण कॉरिडोर पर यात्रा करने वालों को किसी भी टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 270 किलोमीटर का यह पूरा खंड मल्टी लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) सिस्टम के सक्रिय होने के बाद बैरियर-मुक्त होगा, जिससे वाहन फर्राटा भरते हुए आगे बढ़ सकते है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1 अगस्त से हाइवे पर स्थित राजस्थान के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर भी एमएलएफएफ प्रणाली शुरू हो जाएगी। इससे पहले दौलतपुरा और मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर यह आधुनिक प्रणाली पहले से ही काम कर रही थी। शाहजहांपुर 270 किलोमीटर के गलियारे का आखिरी टोल गेट था जहाँ एमएलएफएफ लगना बाकी था। अब इसके भी सक्रिय होने से लाखों यात्रियों को टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम और इंतजार से बड़ी राहत मिलेगी।

मल्टी लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसमें वाहनों को टोल चुकाने के लिए रुकना नहीं पड़ता। इसमें हाई-परफॉर्मेंस आरएफआईडी (आरएफआईडी) रीडर और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाते हैं, जो फास्टैग और वाहन की नंबर प्लेट को तुरंत पढ़ लेते हैं और टोल राशि अपने आप काट लेते हैं। यह प्रणाली यात्रा के समय को काफी कम कर देती है, ईंधन की बचत करती है, टोल प्लाजा के पास होने वाले जाम को खत्म करती है और प्रदूषण को भी घटाने में सहायक होती है।

अधिकारियों का मानना है कि कुकरोला (खेड़की दौला) टोल गेट पर भी आरएफआईडी लगने के बाद जल्द ही दिल्ली से जयपुर तक का पूरा कॉरिडोर बिना किसी बैरियर वाला होगा। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को अपने फास्टैग अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखना अनिवार्य होगा।

10वें दिन भारत की बॉक्सिंग में डबल गोल्ड, प्रीति के बाद जैस्मिन लंबोरिया भी बनीं चैंपियन

वेब वार्ता, ग्लासगो

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश की झोली में एक और स्वर्ण पदक डाल दिया। प्रीति के गोल्ड जीतने के बाद जैस्मिन लंबोरिया ने भी फाइनल मुकाबले में दमदार जीत दर्ज कर भारत को दिन का दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया।

जैस्मिन लंबोरिया ने पूरे मुकाबले में आक्रामक खेल, सटीक पंच और बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी पर शुरूआत से ही दबाव बनाए रखा और निर्णायकों को प्रभावित करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। उनकी इस जीत के साथ भारतीय बॉक्सिंग दल का शानदार अभियान और मजबूत हो गया। इससे पहले भारतीय मुक्केबाज प्रीति ने भी फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। लगातार दो स्वर्ण पदक मिलने से भारतीय दल का मनोबल काफी ऊंचा हो गया है। बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा पूरे टूनार्मेंट में देखने को मिला है और कई अन्य मुक्केबाज भी पदक जीतने की दौड़ में बने हुए हैं।

जैस्मिन और प्रीति की स्वर्णिम सफलता के बाद भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। अब भारत के खाते में 7 स्वर्ण, 13 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 27 पदक हो चुके हैं। इस प्रदर्शन के दम पर भारत पदक तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें अब दिन के बाकी मुकाबलों पर टिकी हैं। बॉक्सिंग के अलावा एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है और माना जा रहा है कि भारत के खाते में अभी और पदक जुड़ सकते हैं।

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026
पदक तालिका
(1 अगस्त 2026, नवीनतम उपलब्ध अपडेट)

रैंक	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	ऑस्ट्रेलिया	26	13	20	59
2	इंग्लैंड	9	14	11	34
3	कनाडा	7	8	6	21
4	स्कॉटलैंड	6	4	3	13
5	नाइजीरिया	6	4	0	10
6	भारत	7	13	7	27
7	मलेशिया	4	1	2	7
8	दक्षिण अफ्रीका	3	3	5	11
9	जमैका	2	0	0	2
10	न्यूजीलैंड	1	5	3	9

भटके युवाओं को सजा नहीं, सही राह दिखाने की जरूरत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने और अपनी दिवंगत मां के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की भाषा किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन में शामिल युवाओं को माफ करने की बात कहते हुए समाज से उन्हें सही दिशा दिखाने और अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार रात अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि बचपन और युवावस्था गलतियों

से सीखने तथा स्वयं को सुधारने का अवसर होती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जंतर-मंतर पर जो कुछ हुआ, उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा। कुछ भटके हुए युवाओं ने मयार्दा की सीमाएं लांघते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया गया और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि इस घटना से समाज में आक्रोश और सांस्कृतिक झटका महसूस किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनका मानना है कि गलती करने वाले युवाओं को सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को कानूनी मामलों या दंडात्मक कार्रवाई में उलझाने से सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसके बजाय समाज की जिम्मेदारी है कि उन्हें सही मार्ग दिखाए और बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे।

वाराणसी से 10 नई उड़ानें शुरू, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा उड़ेंगे विमान

वाराणसी। शनिवार एक अगस्त से वाराणसी एयरपोर्ट से एक-दो नहीं सीधे 10 नई उड़ानों की शुरूआत हो गई। नई उड़ानें शुरू होने से यात्रियों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और विजयवाड़ा जैसे बड़े शहरों के लिए आने-जाने में आसानी होगी। इन उड़ानों में एयर इंडिया एक्सप्रेस सबसे ज्यादा उड़ानें बढ़ाने जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से वाराणसी से मुंबई के लिए दो नई उड़ानें शुरू की। इसके साथ ही दिल्ली के लिए भी एक अतिरिक्त उड़ान शुरू की। इससे दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों को समय के मुताबिक उड़ान चुनने का बेहतर विकल्प मिलेगा। कारोबार और नौकरी के सिलसिले में इन दोनों शहरों के बीच आवागमन करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आकासा एयर वाराणसी से बेंगलुरु के बीच नई उड़ान शुरू करेगी। यह उड़ान हर दिन संचालित होगी। पिछले दिनों दक्षिण भारत के शहरों के लिए सीधी उड़ान कम होने से यात्रियों को परेशानी होने लगी थी। इंडिगो एयरलाइन विजयवाड़ा के लिए नई उड़ान शुरू करेगी। इससे दक्षिण भारत का एक और शहर से काशी का सीधा कनेक्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर 1 अगस्त से 10 नई उड़ानें हवाई अड्डे से जुड़ रही हैं। मौजूदा समय में वाराणसी हवाई अड्डे पर हर दिन 22 विमानों का आना-जाना होता है। इस तरह कुल 44 उड़ानों का संचालन हो रहा है।

एक लाख जहाजों में लगेंगे ट्रांसपोंडर, मछुआरों के सीमा पार करने पर करेगा अलर्ट

वेब वार्ता, नई दिल्ली। समुद्री मछली पकड़ने वाले एक लाख जहाजों में जल्द ही वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम (वीसीएसएस) के तहत ट्रांसपोंडर लगाए जाने की तैयारी है। यह सिस्टम खराब मौसम में मछुआरों के लिए फायदेमंद होगा, जिससे बचाव दल अपने जहाजों का पता लगा सकेंगे। इतना ही नहीं यह मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों को गलती से पड़ोसी देशों की सीमा में जाने से रोकने के लिए अलर्ट भी करेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत वीसीएसएस के लिए नेशनल रोल-आउट प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत 364 करोड़ रुपए है। मछली पकड़ने वाले जहाजों पर ट्रांसपोंडर लगाने के अलावा इस प्रोजेक्ट में जरूरी अर्थ स्टेशन और उससे जुड़े कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और क्षेत्रीय भाषाओं में नभमित्र एप्लीकेशन बनाना शामिल है।

प्रोजेक्ट के तहत योग्य मछुआरों को ट्रांसपोंडर मुफ्त में दिए जाते हैं। इसे केंद्र और राज्यों के बीच 60 :40 के हिसाब से लागत शेयरिंग के आधार पर लागू किया जाना है। केंद्रशासित प्रदेशों को 100 फीसदी केंद्रीय मदद दी जाएगी। वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम को इसरो ने समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी, कंट्रोल और निगरानी के लिए बनाया है। इसरो की ओर से समुद्री मछली पकड़ने वाले समुदाय की मदद के लिए नभमित्र एप्लीकेशन बनाया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कुल 1,547 नोटिफाइड सेंटरों में से 423 फिश लैंडिंग सेंटरों (एफएलसी) पर इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई गई है। एफएलसी को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित राज्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए माना जाता है, जिसमें मछली पकड़ने वाले जहाजों की संख्या, सेंटर पर निर्भर मछुआरों की संख्या, मछली पकड़ने की मात्रा, मछली बाजारों और प्रोसेसिंग सेंटरों से नजदीकी और दूसरी स्थानीय जरूरतें शामिल हैं, जिसमें टेक्नो-फाइनेंशियल वायबिलिटी और कानूनी नियमों का पालन करने के साथ-साथ फाइनेंशियल रिसोर्स की उपलब्धता शामिल है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा एफएलसी 350 आंध्र प्रदेश में हैं, इसके बाद तमिलनाडु में 301 और केरल में 204 हैं।

परिसीमन और महिला आरक्षण बिल: दो-तिहाई वोटों की दीवार पार करने को तैयार मोदी सरकार?

वेब वार्ता, नई दिल्ली

संसद का मानसून सत्र अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका है, और केंद्र की मोदी सरकार की नजर अब दो अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयकों महिला आरक्षण बिल और लोकसभा-विधानसभा सीटों को बढ़ाने वाले परिसीमन विधेयक पर ठीक गई है। एंटी पेपर लीक बिल जैसे महत्वपूर्ण विधायी कामकाज निपटाने के बाद, मोदी सरकार के सामने इन संवैधानिक संशोधनों के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत की चुनौती खड़ी है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और 13 अगस्त तक चलेगा। शुरूआती सप्ताह पेपर लीक और छात्र आंदोलन के विरोध में हंगामे की भेंट चढ़ गए थे, लेकिन दूसरे सप्ताह में मोदी सरकार एंटी पेपर लीक बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रही। अब बचे हुए करीब नौ दिनों में केंद्र सरकार इन दोनों विधेयकों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। चूंकि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल संविधान संशोधन से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरुरत होगी। लोकसभा में कुल 543 सीटों में से तीन रिक्त हैं, इसके बाद 540 सदस्यों में से किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए 360 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है।

मोदी सरकार नहीं अभी तक नहीं खोले हैं अपने महत्वपूर्ण विधेयकों के पत्ते

मोदी सरकार ने पूर्व में भी परिसीमन बिल पेश किया था, लेकिन तब वह आवश्यक बहुमत नहीं जुटा पाई थी। हालांकि, हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों, जैसे तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) से सांसदों के दलबदल ने सरकार के संख्या बल को मजबूत किया है। वर्तमान में, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास करीब 293 सांसद हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ दलबदलुओं और वाईएसआरसीपी के 4 तथा एक निर्दलीय सांसद के समर्थन को मिलाकर, सरकार के पास करीब 324 सांसदों का आंकड़ा होने का अनुमान है। दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 सांसदों की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि सरकार को अभी भी लगभग 36 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। केंद्र की मोदी सरकार की नजर डीएमके के 22 और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) के 8 सांसदों पर थी। हालांकि, एंटी पेपर लीक के मुद्दे पर एनसीपी (एसपी) के आक्रामक रुख को देखकर उनका समर्थन हासिल करना अब मुश्किल प्रतीत हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि मोदी सरकार इन विधेयकों को तभी सदन में लाएगी, जब वह इनके पारित होने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होगी और आवश्यक दो-तिहाई बहुमत का समर्थन जुटा लेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इस बहुमत की दीवार को कैसे पार करती है।

संपादकीय

कंगना के विवाद अर्जित हैं

एक पीढ़ी को जनरेशन गटर का खिताब देने से पहले इस महिला की असंतुलित मानसिकता का अग्रि प्रेक्षपण बहस का विषय बन गया, तो सोचना यह होगा कि हम हिमाचली आखिर चुन कौन सा कबाड़ रहे हैं। मानसिक कबाड़ की हद में हमारी सांसद के किस्से आखिर सारे देश में किस पक्ष की गवाही देते हैं। मंडी की सांसद एक बेहतर अदाकारा होने के कारण कभी करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में राज करती थीं, लेकिन अब नफरती टिप्पणियों के कारण मोहतरमा हाशिए पर दिखाई देती हैं। आखिर ऐसे सांसदों से हासिल क्या है। कम से कम यह मंडी की भाषा नहीं और न ही वोटर की भाषा है। संसदीय स्क्रीन पर कंगना की बादशाहत गलत कारणों से सामने आ रही है और जहां कई वर्गों के खिलाफ यह सांसद जैसे कोई स्वांग कर रही हो। बयानों की लंबी फेहरिस्त में बयान नहीं विवाद अर्जित हैं और मुकदमा यह नहीं कि भाजपा उन्हें सम्मानित कर रही हो। जो चंद नेता भटके हुए हैं, वहां आग बबूला कंगना का किरदार हमेशा कोई न कोई विवाद चुन लेता है। टिप्पणियां, इंटरव्यू और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके फर्ज की अदायगी का आलम यह कि इन्हें स्वयं सिद्धि की अमर्यादित भाषा रास आती है। बेशक राजनीतिक तौर पर एक पक्ष कंगना के साथ रहता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह दूसरे पक्ष पर नफरत का प्रहार करके प्रशंसनीय हो रही हैं। बयानों की एक ऐसी श्रृंखला मोहतरमा के गले से बंधी है जो लोकतांत्रिक छवि को गहरी चोट पहुंचा रही है।

कंगना रनोत के बयानों से जो भूकंप आते हैं, उनसे निकली स्याह चिंयां हिमाचल के वक्तव्यों का परिप्रेक्ष्य बदल देती हैं। अब जंतर मंतर आंदोलन की राख से हमारी सांसद मोहतरमा ने ऐसा बखेड़ा चुन लिया कि लोग गटर में हमारे जनप्रतिनिधियों की भाषा की सड़ांध महसूस करने लगे हैं।

ये हंगामे मेरे साथ चलेंगे, तू न चले या कोई साथ न चले। हमारा मानना है कि इस अदाकारा ने सियासत की घुट्टी पीकर अपना नुकसान ही किया है। इन्हीं हरकतों की वजह से फिल्मी करियर सिमट गया, जबकि सार्वजनिक जीवन में वह राष्ट्रीय बहस का नॉन सीरियस एक्टर बन गई हैं। बेशक कंगना के अपने संघर्ष, अपने मुखौटे होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें हिमाचल के मसलों पर खरा साबित होना है। उन्हीं के चुनाव क्षेत्र मंडी में आपदाओं की आहें सुनी जा रही हैं, तो बतौर सांसद वह बहुत कुछ कर सकती थीं, जो नहीं हुआ। केंद्रीय राहत के दरवाजे से घोषित 15 सौ करोड़ नहीं मिले, तो मोहतरमा बताएं कि वह इस दर्द का वर्णन कैसे करेंगी। बहरहाल भाजपा के गले से लटकी कंगना की तासीर को कैसे और कितना स्वीकार करने का चिंतन होना चाहिए। हिमाचल भाजपा के माथे पर अगर यह टीका स्वीकार्य है, तो स्वागत है। वरना जेन जी को गटर कहने से वह उन माताओं की खिल्ली उड़ा रही हैं, जो समाज और राष्ट्र के आईने में भारत की आशाओं और देश के भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ी की जनक हैं। बेशक नुक्ता चीनी या राजनीतिक बहस में कंगना की आक्रामक अदा हो सकती है, लेकिन उन्हें भारत की परंपराओं, समाज की आशाओं और जनता की पीड़ाओं को दुत्कारने का हक नहीं मिलता। हिमाचल के लिए उनका सांसद होना अगर मंडी की उपलब्धि है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में कंगना को जनसेवा के आधारभूत सिद्धांत सीख लेने चाहिएं। आखिर वह भी तो किसी पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं, तो उसके आचरण का जिक्र जरूर जुबान पर आएगा।

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन: विरोध का पांच हफ्ते का दौर

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में बार-बार पेपर लीक होने की घटनाओं के लिए उनसे इस्ती$फे की मांग उठी थी। अब सरकार पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को सख्त सजा देने का प्रस्ताव कर रही है। यह तथाकथित 'फास्ट-ट्रैक' उपाय असल में पेपर लीक की असली समस्या का समाधान नहीं है। जरा कुछ जरूरी तथ्यों पर गौर करें। युवाओं के पांच हफ्ते तक चले अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शनों ने मोदी सरकार के अहंकार और 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी के अजेय होने के भ्रम को सबसे बड़ा झटका दिया है। पुलिस की बर्बरता से लेकर लोगों की सोच को प्रभावित करने की तमाम तरकीबों तक, सरकार ने नाकाम शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस बार कोई भी तरीका काम नहीं आया। खासकर पिछले एक हफ्ते में, आंदोलन को रोकने की कोशिशें - जैसे 18 जुलाई को जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक का सुबह-सुबह आपत्तिजनक तरीके से उठाकर ले जाना और 20 जुलाई को संसद तक ऐतिहासिक मार्च पर पुलिस की चौंकाने वाली कार्रवाई के बाद मोदीजी की आधी रात को बार-बार वीडियो अपील- उल्टी पड़ गईं और विरोध-प्रदर्शनों की तीव्रता और देशव्यापी विस्तार को और बढ़ा दिया, जिससे सरकार के पास धर्मेंद्र प्रधान की बलि देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा।

हालांकि विरोध आंदोलन ने अपनी सबसे तात्कालिक मांग पूरी कर ली है, लेकिन पूरे भारत में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्याचार और उत्पीड़न में कोई कमी नहीं आई है। सैंकड़ों कार्यकर्ता अभी भी बिहार की जेलों में बंद हैं और लोगों को फंसाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार प्रमुख नेताओं में जेएनयू एसयू के पूर्व महासचिव और पालीगंज से फिर से चुने गए सीपीआई (एमएल) विधायक संदीप सौरभ, जेएनयू एसयू के पूर्व अध्यक्ष धनंजय कुमार, बिहार एआईएसए नेता सबा आफरीन और दीपांकर, पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर और कई अन्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में, भाजपा सरकार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए हाल ही में बने कठोर 'गुंडा दमन कानून' का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें खासकर मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार के साथ सीजेपी की घोषित समझ के अनुसार, यह हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने और उन पर लगाए गए आरोपों और मामलों को वापस लेने के आश्वासन का उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बर बल और पैलेट गन के इस्तेमाल और सादे कपड़ों में लोगों द्वारा आरएएफ कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों की पिटाई करने के भी पर्याप्त दस्तावेजी सबूत हैं। बिहार से पुलिस द्वारा एके-47 असॉल्ट राइफल के इस्तेमाल की खबरें हैं। खबरों के अनुसार, आरएएफ की महानिरीक्षक सीमा धुंधिया ने एक आंतरिक समीक्षा में भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर जरूरत से ज्यादा और अनावश्यक बल के इस्तेमाल को स्वीकार किया है। पुलिस के अपने नियमों के इस खुलेआम उल्लंघन के लिए कौन जवाबदेही लेगा? दिल्ली पुलिस अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, अमित शाह की जवाबदेही और पूरे भारत में युवा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के लिए आम माफी लागू किए बिना आंदोलन के मौजूदा चरण का कोई अंत नहीं हो सकता।

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में बार-बार पेपर लीक होने की घटनाओं के लिए उनसे इस्ती$फे की मांग उठी थी। अब सरकार पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को सख्त सजा देने का प्रस्ताव कर रही है। यह तथाकथित 'फास्ट-ट्रैक' उपाय असल में पेपर लीक की असली समस्या का समाधान नहीं है। जरा कुछ जरूरी तथ्यों पर गौर करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने हाल ही में अपने लगभग 200 कर्मचारियों में से 47 को नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन उनके नाम, पद और लीक में उनकी कथित भूमिका का खुलासा नहीं किया है। जब हर चार में से एक कर्मचारी के लीक में शामिल होने का शक हो, तो यह एनटीए की ईमानदारी पर ही सवाल खड़े करता है। अब समय आ गया है कि एनटीए को भंग कर दिया जाए और उसकी जगह एक नई एजेंसी बनाई जाए, जो संसदीय कानून के तहत काम करे और पारदर्शिता व जवाबदेही के नियमों का पालन करे। ठीक उसी समय जब सरकार फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और सजा बढ़ाने की बात कर रही है, 2024 नीट पेपर लीक के एक मुख्य आरोपी को सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई। और यह भी ध्यान दें कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने 'पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और 'सख्त सजा' दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के सरकार के इरादे की घोषणा की, उसी दिन उनकी सरकार ने राज्यसभा में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए, जिनसे भारत में फास्ट-ट्रैक कोर्ट की असलियत सामने आई। अप्रैल 2026 तक, 775 फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट में 2,49,000 से ज्यादा मामले लंबित थे; इनमें 398 कोर्ट ऐसे थे जो विशेष रूप से 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण' पास्को अधिनियम के तहत मामलों से निपटने के लिए बनाए गए थे। छात्र-युवा आंदोलन सेंट्रलाइज्ड नीट परीक्षा सिस्टम में बदलाव या उसे पूरी तरह बदलने की मांग कर रहा है। यह सिस्टम राज्यों के उस संघीय अधिकार को कमजोर कर रहा है जिसके तहत वे अपनी भाषाई और शैक्षिक स्थितियों को ध्यान में रखकर परीक्षाएं आयोजित कर सकते थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (एनईपी 2020) के भेदभावपूर्ण और कुछ लोगों को बाहर रखने वाले स्वभाव को लेकर भी नाराजगी बढ़ रही है। इस पॉलिसी को कोविड के समय कृषि कानूनों और लेबर कोड के साथ पास किया गया था। नई पॉलिसी ने कम और मध्यम आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए हायर एजुकेशन को बहुत महंगा बना दिया है। साथ ही, चार साल के डिग्री कोर्स के लिए मनमाने नियम छात्रों को डिग्री पूरी करने से पहले ही कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। असल में, एआईएसए और आरवाईए द्वारा 22 जुलाई को पटना में किए गए विरोध प्रदर्शन और 25 जुलाई के बिहार बंद को जो भारी समर्थन मिला, उसके पीछे नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ एनईपी और बिहार की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी भी एक बड़ी वजह थी।

जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में नीट यूजी- 2026 पेपर लीक के कारण 21 छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया गया। सरकार अब पीड़ित परिवारों में से हर एक को मुआवजा देने के लिए सहमत हो गई है। लेकिन कर्ज के बोझ से दबे किसानों की आत्महत्या और महिलाओं द्वारा माइक्रोफाइनेंस से जुड़ी आत्महत्याओं की तरह ही, हाल के वर्षों में छात्रों की आत्महत्या भी एक बहुत चिंताजनक घटना बन गई है। 2021 से 2026 के मध्य तक नीट से जुड़ी कम से कम 93 छात्रों की आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं। अगर नीट से हटकर आम तौर पर छात्रों की आत्महत्याओं को देखें, तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2024 के बीच-यानी भारत में मोदी युग के शुरूआती दस सालों में- 1,23,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। युवाओं के गुस्से या 'जेन जेड' की नाराजगी के पीछे- जिसे हमने हाल ही में सीजेपी के जबरदस्त उभार के जरिए डिजिटल रूप में, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में चुनावी रूप से, या जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शनों के अभूतपूर्व फैलाव और तीव्रता के जरिए सामाजिक रूप से देखा है- अभाव, निराशा और बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने का एक लंबा और विविध पैटर्न मौजूद है। जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से शायद तुरंत तो बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मिले, और साथ ही सार्वजनिक शिक्षा के बेहद जरूरी लेकिन नजरअंदाज किए गए मुद्दे और एक काम करती हुई डेमोक्रेसी में जवाबदेही की अहम भूमिका पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन भारत में 'जेन जी' के विरोध प्रदर्शनों के नए दौर की शुरूआत करके, एक नई जीवंत संस्कृति, आम बोलचाल की भाषा और लोगों के अपनी बात रखने के लगभग त्योहार जैसे माहौल को बनाकर—जिसने नफरत, झूठ, डर और बेरुखी के गहरे जाल को तोड़ दिया है—जंतर-मंतर ने डेमोक्रेसी को फिर से मजबूत करने के नए रास्ते खोल दिए हैं। बिहार और असम सरकारों द्वारा माफी (एमनेस्टी) की घोषणा से पता चलता है कि इस आंदोलन का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस असर को और बढ़ने दें, और समाज के अलग-अलग वर्गों और संघर्ष के मोर्चों के बीच एकता और एकजुटता के नए रिश्ते बनने दें। जंतर-मंतर की भावना को पूरे भारत में फैलने दें और लोगों के अधिकारों के लिए उनके विरोध की आवाज को दूर-दूर तक गूंजने दें।

दीपांकर भट्टाचार्य

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आर पार की लड़ाई

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह की रास्सा-कस्सी देखने को मिल रही है, उससे स्पष्ट है, विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक तेवर में है। जंतर मंतर में हुए कॉकरोच आंदोलन के बाद देश भर के युवाओं में जो गुस्सा देखा गया, देश में सेकड़ों स्थान पर प्रदर्शन हुए। उसने विपक्ष को एक नई ताकत दे दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मौके को आपदा में अवसर के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह से सरकार के खिलाफ जेन-जी और जेन-अल्फा अपने परिवार से विद्रोह करके सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतरा, तरह-तरह से बिना डरे हुए उसने मुखरता के साथ अपनी बात कही। युवाओं के इस आंदोलन को देखकर देश में जो डर और भय का माहौल बना था, ऐसा लगता है कि वह डर और भय खत्म हो गया है। छात्रों के साथ-साथ अब अन्य संगठन भी अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। उनके भी वैसे ही आक्रामक तेवर हैं, जैसे जंतर मंतर में या छात्र आंदोलन के दौरान देखने को मिले थे। इसने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किसान संगठनों ने भोपाल तक मूंग खरीदी को लेकर कूच किया। उन्होंने पुलिस के सारे बैरियर पार करते हुए मुख्यमंत्री निवास के करीब 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। जबकि सरकार ने कई किलोमीटर पहले से ही बेरीकैट लगाकर किसानों को रोकने का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया था। किसानों ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। मध्य प्रदेश सरकार ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। पुलिस अधिकारियों ने भी किसानों को रोकने के लिए जिस तरह से मुंबई की एक जेन-जी लड़की पुलिस वाहन के सामने आकर खड़ी हो गई थी ठीक वैसे ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किसानो की बस के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण किसानों को रुकना पड़ा।

संसद के मानसून सत्र का दूसरा साप्ताह खत्म हो गया है। सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए संसद में जो बिल पेश किया था, वह पास हो गया है। इस बीच संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी और विपक्ष ने अब अपना निशाना गृहमंत्री की ओर कर लिया है। अब इस्तीफा और माफी को लेकर विपक्ष अड़ गया है, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री संसद की कार्रवाई में नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर विपक्ष और आक्रामक हो गया है। संसद परिसर में जिस तरह विपक्षी दल एकत्रित होकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पेलेट गन और एक-47 का मुद्दा दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण विपक्ष ने बुरी तरह से सरकार को घेर लिया है। जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हो रहा था, इसका लाइव प्रसारण होने से पुलिस और सरकार की परेशानी बढ़ रही है। सरकार को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो बिसात विपक्ष बिछा रहा है उसी पर सफाई देने के लिए सरकार को आगे आना पड़ रहा है।

पुलिस के परिवारजनों को मीडिया के सामने उतारा गया है। वही प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के नेताओं का कहना है प्रदर्शन पूर्णतया शांतिपूर्ण था। पुलिस ने साजिश रची थी। इस साजिश का खुलासा भी हो चुका है। ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया में है, जो पुलिस की कलई को खोल रहे हैं। सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए और पुलिस के संरक्षण में जो आसमाधिक तत्व वहां लाये गए थे, वह सब सोशल मीडिया में पुलिस के साजिश की कलई खोल रहे हैं। सरकार को समझ नहीं आ रहा है छात्रों के इस प्रदर्शन और पुलिस का सरकार किस तरह से बचाव करे। राजनीतिक दलों के नेताओं, उनके सांसदों, विधायकों और उनके आंदोलन से निपटना सरकार के लिए आसान होता था। पहली बार सरकार को छात्रों के इस आंदोलन से डर लग रहा है। उसे निकालने का मौका नहीं मिल रहा है। सरकार ने संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्षी दलों के ऊपर बहुत दबाव बनाया, लेकिन विपक्ष अब किसी दबाव में आता हुआ दिख नहीं रहा है। आसंदी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की शर्त रखकर उन्हें बोलने नहीं दिया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषा-अधिकार हनन प्रस्ताव पेश कर दिया है। शुक्रवार को आसंदी से सांसदों को चेतावनी दी जा चुकी है कि वह संसद परिसर में कोई ऐसा प्रदर्शन ना करें जिसके कारण उन पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन यह सारे प्रयास कहीं पर भी कारगर होते हुए दिख नहीं रहे हैं। विपक्ष इस बार आर-पार की लड़ाई लड़ने की मुद्रा में है। उसका एकमात्र लक्ष्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा है। विपक्ष का मानना है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक प्रतीक था। गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा पूरी सरकार को हिलाकर रख देगा। विपक्ष सरकार की आपदा में अपने लिए सबसे बड़ा अवसर देख रहा है। जिस तरह से पिछले 15 दिनों में स्थितियां बदल रही हैं उसने विपक्ष का मनोबल बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष का मनोबल घटा है। सत्ता पक्ष के बीच में संवाद भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के सहयोगी दल चुपचाप बैठे हुए हैं, जो वर्तमान स्थिति का बखान कर रहे हैं।

लेखक- सनत जैन

कब तक कर्ज के सहारे खेती करेगा किसान ?

गांवों में खेती केवल रोजगार नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ज़िंदगी का आधार होती है। हर मौसम के साथ किसान एक नई उम्मीद बोता है। वह बीज के साथ अपने परिवार की कमाई, मेहनत और आने वाले दिनों का भरोसा भी खेत में डालता है। लेकिन कई बार खेती की शुरूआत ही ऐसी मुश्किलों से होती है, जिन पर किसान का कोई नियंत्रण नहीं होता। समय पर बीज न मिलना, खेती की बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता और सरकारी योजनाओं तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ उसकी उम्मीदों को धीरे-धीरे कमजोर कर देती है।

यही कारण है कि जमीन के छोटे टुकड़े पर खेती करने वाला किसान आज केवल मौसम से नहीं, बल्कि व्यवस्था की खामियों से भी संघर्ष कर रहा है। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के अनेक ग्रामीण इलाकों में छोटे किसानों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि उन्हें सरकारी बीज वितरण योजना की जानकारी समय पर नहीं मिलती है या फिर जब वे कृषि विभाग के केंद्रों तक पहुँचते हैं, तब तक बीज का स्टॉक समाप्त हो चुका होता है। कई किसानों के आवेदन अधूरे रह जाते हैं, कुछ तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित रह जाते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो पूरी प्रक्रिया से ही अनजान रहते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें निजी दुकानों से अधिक कीमत पर बीज खरीदना पड़ता है। जिससे उनके खेती की लागत बढ़ जाती है, जबकि आमदनी पहले से ही सीमित होती है। छोटे किसान के लिए कुछ हजार रुपये का अतिरिक्त खर्च भी पूरे परिवार के मासिक बजट को प्रभावित कर देता है। जिन किसानों के पास एक या दो एकड़ से भी कम जमीन है, उनके पास जोखिम उठाने की गुंजाइश सबसे कम होती है। कई परिवार खेती शुरू करने के लिए ही उधार लेते हैं। अच्छी फसल होने पर किसी तरह कर्ज.उतर जाता है, लेकिन नुकसान होने पर वही कर्ज.अगले मौसम तक साथ चलता है। हमारे देश में आज भी ज्यादातर खेती प्रकृति पर निर्भर है और पिछले कुछ वर्षों में मौसम का बदलता स्वरूप किसानों की चिंता और बढ़ा रहा है। कभी अत्यधिक वर्षा खेतों में पानी भर देती है, जिससे तैयार फसल खराब हो जाती है। तो कभी, पर्याप्त वर्षा न होने से सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसी परिस्थितियों में किसान की पूरी मेहनत और निवेश कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाता है। बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर किया गया खर्च वापस नहीं आता, जबकि लिया गया कर्ज.ब्याज के साथ बढ़ता ही जाता है। कई बार किसान को पुराने कर्ज.को चुकाने के लिए नया कर्ज.लेना पड़ता है और वह धीरे-धीरे कर्ज.के ऐसे चक्र में फँस जाता है, जिससे निकलना आसान नहीं होता। हालांकि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। यह सहायता किसानों को खेती की शुरूआती लागत पूरी करने में कुछ हद तक मदद करती है। बिहार में भी लाखों किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 तक राज्य के लगभग 77.7 लाख किसानों का पंजीकरण पीएम-किसान योजना में हो चुका था। इसी अवधि में 14 लाख से अधिक किसानों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से बीज उपलब्ध कराए गए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और सब-मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मैटेरियल के माध्यम से किसानों को प्रमाणित और उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके। बिहार सरकार भी मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, बीज वितरण योजना, कृषि इनपुट अनुदान योजना तथा बिहार राज्य फसल सहायता योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को राहत देने का प्रयास कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों तक बेहतर गुणवत्ता के बीज और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आर्थिक सहायता पहुँचाना है। हालाँकि इन उपलब्धियों के बावजूद यह कहना कठिन है कि योजनाओं का लाभ सभी छोटे किसानों तक समान रूप से पहुंच पाया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन्हें इन योजनाओं की सबसे अधिक जरूरत है, वे ही अक्सर वंचित रह जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या उन भूमिहीन, और महिला किसानों की है जो खेतों में अनवरत काम करते है, कई बार उनसे भी अधिक जिसका जमीन पर मालिकाना है, पर जमीन अपने नाम न होने के कारण उन्हें योजनाओं का लाभ तक नहीं मिलता। अनेक किसानों के आवेदन दस्तावेजों की कमी, आधार या बैंक खाते से जुड़ी तकनीकी समस्याओं अथवा जानकारी के अभाव में लंबित रह जाते हैं। वहीं कई स्थानों पर बीज की आपूर्ति समय पर नहीं होने से किसानों को निजी दुकानों से अधिक कीमत पर बीज खरीदना पड़ता है। इससे सरकारी योजना का उद्देश्य पूरी तरह सफल नहीं हो पाता।

विशेषज्ञ भी मानते हैं कि केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि खेती के पूरे चक्र को मजबूत बनाया जाए। समय पर प्रमाणित बीज की उपलब्धता, मौसम के अनुरूप वैज्ञानिक सलाह, आसान फसल बीमा, त्वरित मुआवजा और किसानों तक सही जानकारी पहुँचाने की व्यवस्था एक साथ मजबूत करनी होगी। पंचायत स्तर पर बीज वितरण केंद्रों की निगरानी बढ़ाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सीमित भूमि वाले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर बीज उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, आवेदन प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाए कि कम पढ़े-लिखे किसान भी बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ उठा सकें।

देश की खाद्य सुरक्षा की नींव छोटे किसानों के कंधों पर टिकी है। यदि वही किसान हर मौसम की शुरूआत कर्ज.लेकर करेगा और हर फसल के बाद और अधिक कर्जदार होता जाएगा, तो खेती का भविष्य भी असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए समय की मांग है कि सरकारी योजनाओं की सफलता केवल लाभार्थियों की संख्या से नहीं, बल्कि इस आधार पर मापी जाए कि क्या सबसे कमजोर किसान तक समय पर बीज, पर्याप्त सहायता और भरोसेमंद सुरक्षा पहुँच रही है?

सुनिधि कुमारी, मुजफ्फरपुर, बिहार

आलेख

युवाओं के सत्याग्रह ने अपने पीछे कुछ सबक छोड़े

आंदोलन ने सत्ता में बैठे लोगों को अपनी कार्यशैली में जरूरी बदलाव पर विचार का मौका दिया है। सत्ता के दुरुपयोग, उसके केंद्रीकरण के खिलाफ लोगों के उठ खड़े होने के बारे में चेतावनी दी है। प्रधान के इस्तीफे से निश्चय ही दूसरे मंत्री सतर्क हो जाएंगे। दरअसल, यह सुरक्षा के अघोषित और अदृश्य कवच में दरार आने का संकेत है। भाजपा सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होने का मिथक टूट गया है।

जंतर-मंतर पर एक माह तक चले युवाओं के आंदोलन ने कुछ सबक सिखाए हैं, कुछ मुद्दों पर रोशनी डाली है, कुछ उम्मीदें जगाई हैं और साहस, सत्याग्रह की अहमियत को सामने रखा है। यह आंदोलन कई मायनों में अद्वितीय है। उसने लोकतंत्र, संविधान के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी और सत्ता का दुरुपयोग करने वाली सरकार को अपने कदम पीछे हटाने के लिए विवश किया है। इससे पहले किसान आंदोलन के कारण सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेना पड़े थे। लेकिन दोनों आंदोलनों में कुछ फर्क है। किसान आंदोलन का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तरप्रदेश में अधिक था। वहीं युवाओं की हलचल तेजी से फैल रही थी। उसमें छात्रों के परिजन शामिल हो रहे थे। भाजपा का समर्थन करने वाले मध्यम वर्ग में भी बेचैनी थी।

बहुत कम लोगों को शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की उम्मीद थी। राजनीतिक पर्यवेक्षक सत्ताधारी दल के एक वरिष्ठ नेता के बयान का जिक्र करते थे कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। संतोष का विषय है कि युवाओं ने सरकार को जवाबदेही और जिम्मेदारी का अहसास कराया है। उनके आंदोलन के कारण पहली बार शिक्षा राजनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में आ गई है। छात्रों ने संदेश दिया है कि अब भी अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से मनमानी करने वाली सरकार पर अंकुश लगाना संभव है। शासकों के इशारों पर चलने वाली संस्थाओं को सचेत होने का अवसर दिया है।

भारत में संवाद, विरोध और अहिंसक तरीके से अपनी अपेक्षाओं को जाहिर करने की परंपरा पुरानी है। इसके सबसे बड़े प्रतीक महात्मा गांधी हैं। उनके सत्याग्रह ने भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद कई मौकों पर जनमत जगाने वाले आंदोलन हुए हैं। 1970 के दशक में गुजरात से शुरू हुए छात्रों के नवनिर्माण आंदोलन ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की जमीन तैयार की थी। फिर 2011-12 के अन्ना आंदोलन ने यूपीए सरकार की चुनावी हार का रास्ता बनाया। इन आंदोलनों में गैर-राजनीतिक संगठनों, आम लोगों के अलावा राजनीतिक दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

छात्रों के मौजूदा आंदोलन के पीछे सुनियोजित रणनीति और कार्यक्रम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई। उसने दिल्ली में धरना शुरू किया और इसकी गूंज पूरे देश तक पहुंच गई। चंद दिनों के भीतर हजारों युवा दिल्ली में जुट गए। सरकार के दमन ने आग में घी डाला। पुलिस ने आंसू गैस, पैलेट गन, लाठीचार्ज के जरिये जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। इंटरनेट बंद करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युवा शक्ति की क्रिएटिविटी से उपजे हास्य, व्यंग्य की पैनी धार के सामने तमाम तरीके बेअसर हो गए। छात्रों के पोस्टर और मीम भारी पड़े। सोशल मीडिया ने आंदोलन की हलचल को हर जगह पहुंचा दिया।

सरकार की जी-हुजूरी करने और विपक्षी पार्टियों को हमेशा निशाना बनाने वाले गोदी मीडिया के पैंतरे बेकार गए। आंदोलन का स्वरूप और उसकी रफ्तार सरकार की कल्पना से परे थी। उसने छात्रों से लगातार बातचीत की। लेकिन छात्र अपने रुख पर अडिग रहे। आंदोलन के पीछे पाकिस्तान, चीन का हाथ होने जैसे पुराने नकारात्मक दांव भी काम नहीं आए। विरोध को देशद्रोह और राष्ट्रविरोधी बताने का जाना-पहचाना हथियार भी कुंद साबित हुआ। यहां प्रमुख विपक्षी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने छात्रों का समर्थन करने के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखने की सावधानी बरती। इस चतुराई के कारण आंदोलन को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित घोषित नहीं किया जा सका है। सोनम वांगचुक के लंबे अनशन ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया।

छात्रों के विरोध ने शिक्षा व्यवस्था की कई मूलभूत समस्याओं, उच्च शिक्षण संस्थाओं की नियुक्तियों में पेशेवर मापदंडों को दरकिनार रखने सहित कई खामियों पर फिर बहस की जरूरत बताई है। पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थाओं में अहम पदों पर नियुक्तियों में योग्यता, विद्वता, पेशेवर क्षमता की बजाय विचारधारा को तवज्जो दी गई है। स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव पर भी विचारधारा हावी है। परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गहराते संकट ने छात्रों को उद्वेलित किया है। साल दर साल तैयारियों के बाद जब पेपर लीक हो जाएं, समय पर रिजल्ट आने का कोई भरोसा न रहे तब असंतोष का विस्फोट होना स्वाभाविक है।

सत्याग्रह ने शिक्षा और रोजगार से जुड़

संक्षिप्त वार्ता

विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल भाषा के लिए माफी नहीं मांगेंगे : आइसा

नई दिल्ली, 01 अगस्त (वेब वार्ता)। आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने प्रदर्शनकारियों द्वारा केंद्र सरकार की तीखी आलोचना में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए माफी मांगने या उसकी निंदा करने से इनकार कर दिया है। नेहा ने आलोचकों पर आरोप लगाया कि वे 20 जुलाई की कार्रवाई के दौरान पैलेट गन और पुलिस बल के इस्तेमाल से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

नेहा ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों की भाषा को लेकर हो रहे विवाद का इस्तेमाल संसद मार्च वाले दिन पुलिस की कार्रवाई पर जवाबदेही के मुद्दे को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रदर्शनकारी 15 साल की लड़की है, जिसने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की थी, जिससे वह विवाद के केंद्र में आ गई और उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं।

दिल्ली बार काउंसिल चुनाव में डीके शर्मा बने सदस्य

नई दिल्ली, 01 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव में तीस हजारी कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा (डीके शर्मा) ने जीत दर्ज कर बार काउंसिल के सदस्य के रूप में अपनी जगह बनाई है। उनकी जीत के बाद दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। इस बार दिल्ली बार काउंसिल चुनाव में कुल 221 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 25 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिनमें 18 पुरुष और 7 महिला सदस्य शामिल हैं। डीके शर्मा ने 2,323 वोट हासिल कर पुरुष वर्ग में 15वां स्थान प्राप्त किया और सदस्य निर्वाचित हुए।

डीके शर्मा वर्तमान में तीस हजारी कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वह दिल्ली जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति (कोऑर्डिनेशन कमेटी) के अध्यक्ष भी हैं। उनकी जीत पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। जीत के बाद डीके शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, परिवार, समर्थकों और दिल्ली के अधिवक्ताओं को दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह अधिवक्ताओं के हितों की मजबूती से आवाज उठाएंगे और बार व बेंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

दिल्ली पुलिस ने पंजाबी बाग में हत्या के प्रयास में वांछित बदमाश को दबोचा

नई दिल्ली, 01 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी बाग थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपी सुल्तानपुरी निवासी धीरज उर्फ जुडी (24) को गिरफ्तार किया है। आरोपी धीरज अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है और वर्तमान में दिल्ली के अमन विहार क्षेत्र में किराये पर रह रहा था। इसके खिलाफ पहले से 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 30 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता दीपक, पश्चिम पुरी, दिल्ली में अपने फूड कार्ट पर मौजूद था। रात करीब 9:15 बजे कुछ हमलावर पीछे से आए और धारदार हथियार से उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। पुलिस को पता चला कि आरोपी धीरज उर्फ जुडी अपने सहयोगियों के साथ हत्या के प्रयास के मामले में शामिल था। इससे पहले, पांच आरोपी ऋतिक उर्फ माया, अमित, करण, विशाल और बिरजू को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि धीरज उर्फ जुडी और अन्य सहयोगी फरार थे।

आसमान में 2 से 16 अगस्त तक नहीं उड़ेंगे ड्रोन

छोटे हवाई प्लेटफॉर्म पर भी लगा पूर्ण प्रतिबंध

वेब वार्ता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राजधानी में 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन सहित सभी तरह के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सुरक्षा खतरों की आशंका और खुफिया इनपुट के मद्देनजर लिया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया यह आदेश 15 दिनों तक लागू रहेगा। इसमें 15 अगस्त के समारोह से पहले और तुरंत बाद की अवधि शामिल है।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, ऐसी खबरें मिली हैं कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में भी आशंका जताई गई है कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी ड्रोन और अन्य छोटे हवाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आम लोगों, वीआईपी, संवेदनशील सरकारी भवनों और स्वतंत्रता दिवस समारोह को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे किसी भी खतरे को पहले ही खत्म करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। बीएनएसएस के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया कि अधिसूचित अवधि के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी इन चीजों को उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ऊपर पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंगग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि जैसे गैर-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर रोक लगाई जाती है।

वापस नहीं ले लिया जाता

दिल्ली पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 31 जुलाई को जारी किया गया था और इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि यह 2 अगस्त से प्रभावी होगा और 16 अगस्त तक (दोनों दिन शामिल) 15 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा या जब तक कि इसे वापस नहीं ले लिया जाता।

एनएच-48 पर धौला कुआं व रक्षा क्षेत्र के पास दूर होगी जाम की समस्या

एनएच-48 पर धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बने टी-जंक्शन और रक्षा क्षेत्र के निकट स्थित टी-जंक्शन पर रोज लगने वाले भीषण जाम से जल्द राहत मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एनएच-48 के इस के चौड़ीकरण की योजना तैयार की है।

नई दिल्ली,वेब वार्ता

इस कार्य पर करीब 9.44 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो धौला कुआं के रास्ते दिल्ली से गुरुग्राम जाते व आते हैं।

एनएचएआई के अनुसार, एनएच-48 पर धौला कुआं और रक्षा क्षेत्र के पास जाम की समस्या है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को सीमित जगह के कारण यहां सुबह-शाम पीक आवर्स में लंबा जाम झेलना पड़ता है। जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों तक को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस प्रभावित हिस्से की लंबाई करीब 2.9 किलोमीटर है।

धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास टी-जंक्शन को सुधारा जाएगा। साथ ही धौला कुआं से इस जंक्शन तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र के पास राजमार्ग के हिस्से को चौड़ा किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में टी-जंक्शन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क चौड़ी होने से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और जंक्शन पर लगने वाला जाम काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे न सिर्फ आम राहगीरों को राहत मिलेगी बल्कि सड़क हादसों की आशंका भी घटेगी।

एनएचएआई टी-जंक्शन को सुधारने के साथ सड़क का चौड़ीकरण करेगा

हज-2027 की तैयारियां शुरू

चयनित यात्रियों को 1.52 लाख रुपये अग्रिम राशि जमा करने के निर्देश

नई दिल्ली, 01 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली प्रदेश हज कमेटी ने हज-2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑनलाइन कुर्रा (लॉटरी) प्रक्रिया के बाद दिल्ली के 2706 लोगों का हज यात्रा के लिए चयन हुआ है। चयनित सभी यात्रियों को 10 अगस्त तक प्रति व्यक्ति 1,52 लाख रुपये की अग्रिम हज राशि जमा करानी होगी। समय पर राशि जमा नहीं करने पर हज सीट रद्द हो सकती है।

हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी ने बताया कि अग्रिम राशि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा की जा सकती है। अंतिम तिथि तक भुगतान नहीं करने वालों की सीट निरस्त हो सकती है। राशि जमा करने के बाद यात्रियों को हज आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति, रंगीन फोटो, शपथ पत्र, कैंसिल चेक, पासपोर्ट की फोटोप्रति, चिकित्सा प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज हज मंजिल स्थित कार्यालय में जमा करने होंगे, जिसके लिए अलग से सूचना दी जाएगी। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने चयनित यात्रियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के लिए कमेटी पूरी तरह तैयार है।

अभाविप के आंदोलन का असर डीयू में एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों की सीटें दोगुनी

नई दिल्ली, वेब वार्ता

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के छात्रहित में किए गए आंदोलन का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने एक वर्षीय परास्नातक (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने की सिफारिश की थी। समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीटों की संख्या दोगुनी करने का फैसला लिया। साथ ही, कॉलेजों को उनकी आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सीटों में अतिरिक्त वृद्धि करने की अनुमति भी दी गई है।

इस निर्णय का स्वागत करते हुए अभाविप ने इसे छात्रहित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। संगठन का कहना है कि सीटों में बढ़ोतरी से अधिक योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश का अवसर मिलेगा और विश्वविद्यालय में प्रवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।

अभाविप के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि परिषद के आंदोलन के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने का निर्णय छात्र समुदाय की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि स्थापना काल से ही अभाविप 'ठीक करेंगे तीन काम 'प्रवेश, परीक्षा और परिणाम' के ध्येय के साथ कार्य कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह निर्णय योग्य छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करेगा।

लिया गया निर्णय

उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई को अभाविप ने इस मांग को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष व्यापक प्रदर्शन किया था। आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अब यह निर्णय लिया गया है।

फर्जी पैकर्स एंड मूवर्स के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पदार्फाश

नई दिल्ली, 01 अगस्त (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाना पुलिस ने फर्जी पैकर्स एंड मूवर्स के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पदार्फाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक व्यक्ति से डिलीवरी के नाम पर उसका घरेलू सामान और पैसे हड़प लिये थे। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान गुरुग्राम निवासी अजय कुमार सिंह के रूप में हुई है। उसके खिलाफ लक्ष्मी नगर निवासी एक व्यक्ति ने 12 जुलाई को एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसने दिल्ली से बिहार अपना घरेलू सामान भेजने के लिए स्पेस लॉजिस्टिक्स पैकर्स एंड मूवर्स की सेवाएं ली थीं। कंपनी के प्रतिनिधियों ने 1 जुलाई और 8 जुलाई को उसके घर से पूरा सामान उठा लिया। फिर डिलीवरी के नाम पर अतिरिक्त 20 हजार रुपये की मांग की। पैसे मिलने के बावजूद उसने न तो सामान पहुंचाया और न ही रकम लौटाई। पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर शिकायतकर्ता का पूरा घरेलू सामान बरामद किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि अजय शकरपुर थाने में दर्ज एक अन्य आपराधिक मामले में भी वांछित था। पुलिस गिरोह के अन्य आरोपियों का पता लगा रही है।

आईपीयू के स्पोर्ट्स कोटा में आवेदन की अंतिम तिथि आज

नई दिल्ली, 01 अगस्त (वेब वार्ता)। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपीयू) में स्पोर्ट्स कोटा दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दो अगस्त है। इच्छुक छात्र आज आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रोग्रामों में स्पोर्ट्स कोटा उपलब्ध है। इन प्रोग्रामों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। प्रत्येक प्रोग्राम में इस कोटा के लिए एक-एक अतिरिक्त सीट निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ 2,500 रुपये का शुल्क भी जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। भरे हुए फॉर्म विश्वविद्यालय के द्वारका कैंपस स्थित सुविधा केंद्र में दो अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं।

बारिश में डेंगू की दस्तक लापरवाही पड़ सकती है भारी

नई दिल्ली, 01 अगस्त (वेब वार्ता)। राजधानी में मानसून के दौरान तेज बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों के अनुसार, इस मौसम में हर बुखार को वायरल समझकर घर पर दवा लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह डेंगू का शुरूआती संकेत भी हो सकता है। देरी से जांच और इलाज से हालत गंभीर हो सकती है, इसलिए लगातार तेज बुखार होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें।

जलभराव से एडीज मच्छरों का प्रजनन बढ़ने से डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू के लक्षण तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, उल्टी और लाल चकत्ते हैं। शुरूआत में वायरल जैसे लगते हैं।

गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डॉ. प्रवीण कुमार ने कहा कि दो दिन से अधिक बुखार रहने पर जांच कराएं। डेंगू की समय पर पहचान से जटिलताओं से बचा जा सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक न लें। अगर बुखार के साथ कमजोरी, उल्टी, सांस की परेशानी या रक्तस्राव हो तो तुरंत अस्पताल जाएं।

जेएनयू के छात्र पढ़ेंगे नशा मुक्ति का पाठ

नई दिल्ली, 01 अगस्त (वेब वार्ता)। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों को नशा मुक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए दो अगस्त से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान शुरू होगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। विश्वविद्यालय ने सर्कुलर जारी कर सभी स्कूलों, केंद्रों व विभागों को जागरूकता कार्यक्रम, शपथ, रैली, पोस्टर-स्लोगन प्रतियोगिता, व्याख्यान, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

डीयू में स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए सोमवार से खुलेगी मिड एंट्री

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) 2026 के तहत अब तक दाखिले लेने से चूके छात्रों के लिए राहत की खबर है। ऐसे छात्र अब मिड एंट्री के माध्यम से सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं। डीयू सोमवार को मिड एंट्री का विकल्प खोलने जा रहा है। बीते सप्ताह दूसरी आवंटन सूची के दाखिले संपन्न होने के बाद भी अभी कुछ कोर्सेज में कुछ सीटें शेष हैं। ऐसे में अब उन छात्रों को मौका मिलेगा जो कि सीएसएएस में 26 जून से 11 जुलाई तक आवेदन (पहला चरण) करने से चूक गए थे। मिड एंट्री के तहत तीन अगस्त से पांच अगस्त रात 11:59 मिनट तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके साथ ही छात्र अपने ब्यौरे में सुधार भी कर सकेंगे। मिड एंट्री के लिए छात्रों को एक हजार रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। सीट आवंटन की तीसरी सूची आठ सितंबर को जारी की जाएगी। मालूम हो कि दो आवंटन सूची के बाद डीयू की 71, 624 सीटों पर अब तक 71,400 से अधिक दाखिले हो चुके हैं। कई कॉलेजों में कुल सीटों से अधिक दाखिले हुए हैं। जबकि 32 हजार से अधिक छात्र अपनी सीट से संतुष्ट होकर उसे फ्रीज कर चुके हैं। जबकि 25 हजार से अधिक ने सीट को अपग्रेड करने का विकल्प लिया है।

अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली प्रीमियर लीग का रंगारंग आगाज

नई दिल्ली, 01 अगस्त (वेब वार्ता)। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) का शुक्रवार को भव्य आगाज हुआ। मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पुरानी दिल्ली छह को चार विकेट से हराकर टूनार्मेंट में विजयी शुरूआत की। पहले बल्लेबाजी करते हुए पुरानी दिल्ली छह ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 202 रन बनाए। कप्तान अनुज रावत ने 59 गेंदों पर नाबाद 105 रन (11 चौके, 5 छक्के) की शानदार पारी खेली, जबकि देव लाकड़ा ने 37 गेंदों पर 53 रन बनाए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी की। 203 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने तेज शुरूआत की। कप्तान यश धुल ने 45 गेंदों पर 72 रन बनाए। वंश बेदी (13 गेंद, 28 रन) और केशव डबास ने अंतिम ओवरों में दबाव संभाला। डबास ने पेनल्टीमेट ओवर की आखिरी दो गेंदों पर लगातार चौके लगाए, जबकि जसवीर सेहरावत ने आखिरी ओवर में विजयी रन बनाकर टीम को चार विकेट से यादगार जीत दिलाई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरूआत की, पोर्टल का किया शुभारंभ

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना की आधिकारिक शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने पूर्वी दिल्ली स्थित जिलाधिकारी कार्यालय (डीएम ऑफिस) में आयोजित कार्यक्रम में योजना के ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना आर्थिक सहायता से आगे बढ़कर महिलाओं को बचत, डिजिटल वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता से जोड़ने वाला देश का एक अभिनव मॉडल बनेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का जो संकल्प लिया था, आज उसे धरातल पर उतार रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को महिला समृद्धि योजना के नाम से स्वीकृति प्रदान की गई थी, बाद में महिलाओं के सम्मान, समृद्धि एवं आर्थिक सशक्तीकरण की व्यापक भावना को ध्यान में रखते हुए इसका नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक चरण में यह योजना तीन वर्षों के लिए लागू की जाएगी और इससे लगभग 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता

उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य के लिए आर्थिक बचत भी सुनिश्चित कर सकेंगी।

उन्होंने बताया कि योजना को पारंपरिक नकद सहायता योजनाओं से अलग स्वरूप दिया गया है। लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दो वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले विकल्प में प्रत्येक माह 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट में उपलब्ध होंगे, जिनका उपयोग दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा, जबकि शेष 1,500 रुपये आरडी एवं एफडी में जमा होंगे। दूसरे विकल्प में संपूर्ण 2,500 रुपये प्रतिमाह आरडी एवं एफडी में जमा किए जाएंगे, जिससे समय के साथ ब्याज सहित पर्याप्त बचत तैयार होगी। इस प्रकार योजना महिलाओं को तत्काल आर्थिक सहायता के साथ-साथ दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी धन का उपयोग केवल परिवार की आवश्यक जरूरतों के लिए सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीसी वॉलेट में डिजिटल नेगेटिव लिस्ट लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थों, लॉटरी टिकट, जुआ, सट्टेबाजी और सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए नहीं किया जा सकेगा। इससे सरकारी सहायता का उपयोग परिवार के हित में सुनिश्चित होगा।

रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली लक्ष्मी योजना पूरी तरह से तकनीक आधारित और डिजिटल व्यवस्था पर संचालित होगी। इसके लिए लॉन्च किया गया डीएलवाई पोर्टल आवेदन, दस्तावेज वेरीफीकेशन, पात्रता परीक्षण, अनुमोदन, पीएफएमएस एकीकरण, बैंकिंग सेवाएं, सीबीडीसी ट्रांसफर और एसएमएस जैसी सभी सेवाओं को एकीकृत करेगा। इससे पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। प्रत्येक आवेदन को स्वीकृति से पूर्व चार स्तरों की जांच एवं अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट आवेदन की जांच करेगा। इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

संक्षिप्त वार्ता

देवरिया में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड में दो बदमाश गिरफ्तार, एक को लगी गोली

वेब वार्ता, देवरिया

देवरिया जिले के खुखुन्दू क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी।

पुलिस के अनुसार देवरिया के खुखुन्दू थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने महिला से मंगलसूत्र छीनने की वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। जबकि दूसरे को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया।वही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे (315 बोर), 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल, महिला से छीनी गई सोने की माला मय लॉकेट बरामद की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने बताया कि इस टीम का नेतृत्व खुखुंदू थाना के प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह ने किया। जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश कलीम शेख निवासी मोहन मुंडेरा थाना रामपुर को पैर में गोली लग गई और वह मौके पर ही गिर गया।

सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का जनपद में भव्य स्वागत

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश शासन के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जेपीएस राठौर का शनिवार को बलरामपुर जनपद की सीमा पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस

दौरान कार्यकताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया तथा जोरदार स्वागत करते हुए जनपद आगमन पर शुभकामनाएं दीं। स्वागत कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ.आरती तिवारी,सदर विधायक पल्टूराम,तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल,उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा,नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉ.धीरेन्द्र प्रताप सिंह ह्यधीरूह्न,भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह,राकेश सिंह,चन्द्र प्रकाश सिंह ह्यगुड्डूह्न,अनूप चन्द्र गुप्ता,जिला उपाध्यक्ष वरुण सिंह ह्यमोनूह्न,संजय शुक्ल,जिला महामंत्री डॉ. अजय सिंह ह्यपिंकूह्न,डीपी सिंह बैस,राधेश्याम वर्मा सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यकताओं में उत्साह का वातावरण देखने को मिला तथा सभी ने सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का गर्मजोशी से स्वागत कर उनके सफल एवं जनकल्याणकारी कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

एचआईवी जागरूकता के लिए देवरिया में 'रेड रन मैराथन' आयोजित

देवरिया, (वेब वार्ता)। एचआईवी एवं एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार सुबह स्वर्गीय रवींद्र किशोर शाही स्टेडियम में 'रेड रन मैराथन' का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से यूथ फेस्ट सप्ताह के तहत आयोजित पांच किलोमीटर की मैराथन का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार गुप्ता और जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर किया।

मैराथन में पुरुष वर्ग के 76 और महिला वर्ग की 32 प्रतिभागियों सहित कुल 108 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में अभिषेक कुमार ने प्रथम, रितेश निषाद ने द्वितीय और रोहित यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि शंभु कुमार को सांत्वना पुरस्कार मिला। महिला वर्ग में काजल पासवान प्रथम, आंचल पासवान द्वितीय और पूजा पांडे तृतीय रहीं। प्रीति चौरसिया को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। विजेताओं को 2500, 2000, 1500 तथा 500 रुपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में दिशा के क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर डॉ. नीतीश राय ने एचआईवी संक्रमण के कारणों, बचाव के उपायों और नाको हेल्पलाइन 1097 के उपयोग की जानकारी दी। वहीं, एचआईवी-टीबी समन्वयक चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने एचआईवी-टीबी सह-संक्रमण, टीबी के लक्षणों तथा समय पर जांच और उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर हाल ही में आयोजित एचआईवी जागरूकता क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने युवाओं से जागरूक होकर समाज में एचआईवी के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने और समय पर जांच एवं उपचार अपनाने का आह्वान किया।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम का सख्त रुख

राजस्व लापरवाही पर लेखपाल, कानूनगो और आरके का वेतन रोका, निलंबन की चेतावनी

वेब वार्ता, ललितपुर

तहसील महरौनी में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई ने आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान राजस्व विभाग से जुड़ी बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित लेखपालों, कानूनगो तथा आरके (रिकॉर्ड कीपर) मुन्नीलाल का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाएगा। सम्पूर्ण समाधान दिवस में अवैध कब्जा, भूमि विवाद और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों पर जिलाधिकारी ने राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों को तत्काल मौके पर भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, जबकि शेष मामलों के निस्तारण के लिए समयसीमा तय की गई। जनसुनवाई के दौरान अधिकांश शिकायतें परवाने खतौनी में दर्ज न होना, वरासत लंबित रहना, पैमाइश और अवैध कब्जों से संबंधित मिलीं। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित लेखपालों और कानूनगो को फटकार लगाई। उन्होंने उपजिलाधिकारी महरौनी को इन कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आरके मुन्नीलाल को भी कड़ी फटकार लगाते हुए लंबित परवानों को तत्काल खतौनी में दर्ज कर किसानों को उनकी खतौनी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि लापरवाही जारी रही तो उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने क्षेत्र में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह बाद वह स्वयं तहसील का पुन: निरीक्षण करेंगे। यदि निरीक्षण के दौरान कार्यों में सुधार नहीं मिला और जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं तो उसी दिन संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनावश्यक विलंब या आमजन का उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण समाधान कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

अवैध मांग का लगाया आरोप

सम्पूर्ण समाधान दिवस में बम्हौरी बहादुर सिंह निवासी हरीराम तथा दरौना निवासी रामेश्वर ने एक वर्ष से भूमि का परवाना खतौनी में दर्ज न होने की शिकायत की। वहीं दरौनी निवासी भैयन अहिरवार ने परवाना कम्प्यूटर पर दर्ज न करने और अवैध धन की मांग किए जाने का आरोप लगाया।

इनकी रही उपस्थिति

जिलाधिकारी ने तहसीलदार महरौनी को जांच कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा पड़वां निवासी मंजू सहरिया ने अपने लकवाग्रस्त पति का नाम अंत्योदय राशन कार्ड में जोड़ने की मांग की, ताकि उनका आयुष्मान कार्ड बन सके और उपचार हो सके। इस पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक जांच कर पात्रता के अनुसार अंत्योदय कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिले की पांचों तहसीलों में कुल 250 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 31 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान उपजिलाधिकारी महरौनी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, जिला बंदोबस्त अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी सहित पूर्ति, डूडा, ग्राम्य विकास, जल निगम, जल संस्थान, विद्युत एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मोमबत्ती फैक्टरी में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू

मुरादाबाद, वेब वार्ता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के बुध बाजार स्थित मोहल्ला सागर सराय में बनी मोमबत्ती फैक्टरी और उसके गोदाम में बीती देर रात्रि शुक्रवार को आग की भीषण लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली की जिसने फैक्टरी और गोदाम को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। आग की तपिश और धुआं आस पास के घरों में पहुँचने लगा। इससे क्षेत्र में काफी अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर दमकल कर्मी व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बिना देर किए पहुंच गई। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस एवं अग्निशमन विभाग ने तत्काल प्रभाव से राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया। आग की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर सभी उपलब्ध फायर टेंडरों को तत्काल घटनास्थल पर लगाया गया। फायर सर्विस, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों ने पूरी रात लगातार अभियान चलाकर आग को फैलने से रोका तथा आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखा।आग इतनी भयावह थी कि मौके पर 50 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पानी आग बुझाने में लग गई।

अब ग्राम प्रधान अग्रदूत बन कर करेंगे ग्रामीणो को यातायात नियमो के प्रति जागरूक

कानपुर। सड़क दुर्घअनाओ में कमी लाने के उद्देश्य से उ.प्र. शासन ने अब ग्राम प्रधानो को अग्रदूत बना कर ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा नियमो के लिए जागरूक करने का काम दिया है। अब ग्राम प्रधान अग्रदूत बन कर ग्रामणो को सड़क सुरक्षा नियमो के प्रति जागरूक करेंगे।

एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि उ.प्र. के मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देश के क्रम में परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने प्रदेश के सभी जनपदो में आने वाले विकास खण्ड के अर्न्तगत आने वाले ब्लॉको में अबं ग्राम प्रधान सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घअनाओ में कमी लाने के लिए ग्रामीणो को हेलमेट लगने , कार चलाते समय सीट बेल्ट बांधने और वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग न करने के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करेंगे। इसके साथ ही एक समिति बनेगी जिसमें सबसे अच्छा कार्य का प्रदर्शन करने वाले ग्राम प्रधान को अग्रदूत के खिताब से नवाजा जायेगा और उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया जायेगा। इस योजना के तहत अब ग्रामीणो में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता के प्रति जन जागरूकता विकसित होगी और ग्रामीण क्षेत्रो से निकल कर हाइवे पर वाहन चलाते समय नियमो का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आयेगी।

हरदोई में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निदेर्शानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश माननीय रीता कौशिक एवं प्रभारी सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) श्रीमती स्मिता गोस्वामी के निर्देशन में शनिवार को जिला महिला अस्पताल हरदोई में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर नवजात शिशुओं को मातृ स्तनपान के प्रति जागरूकता, मानसिक रोग एवं बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के कानूनी अधिकार तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से बचाव विषयक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति सदर हरदोई के सचिव/तहसीलदार श्री सचिंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन में हुआ। शिविर की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुबोध सिंह ने की।

शिविर में बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य माताओं और समाज को नवजात शिशु के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। परिवार नियोजन काउंसलर गरिमा शुक्ला ने जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने, कोलोस्ट्रम (पहला गाढ़ा पीला दूध) के महत्व, छह माह तक केवल मातृ दूध देने तथा स्तनपान से शिशु एवं माता दोनों को होने वाले स्वास्थ्य लाभों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार अपनाने की भी सलाह दी।

शिविर में लीगल एड क्लीनिक के श्यामू सिंह ने मानसिक रोग एवं बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों को गरिमा के साथ जीवन, समान अवसर, समुदाय में रहने, उचित स्वास्थ्य सेवाएं तथा नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 एवं 39ए तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत इन अधिकारों का संरक्षण किया गया है। उन्होंने नशीले पदार्थों, शराब एवं तंबाकू के दुरुपयोग से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए लोगों से नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नि:शुल्क विधिक सहायता एवं टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अस्पताल स्टाफ एवं बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग कर जागरूकता संबंधी जानकारी ली।

प्रेम संबंध बना संडीला में दोहरे हत्याकांड की वजह, पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। संडीला थाना क्षेत्र में 30 जुलाई को अतरौली मार्ग स्थित निमार्णाधीन जल जीवन मिशन की पानी की टंकी के पास मिले दो युवकों के शवों के मामले का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, मृतकों के दो मोबाइल फोन तथा दो बांस के डंडे बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार 30 जुलाई की सुबह डायल-112 पर सूचना मिली थी कि तकिया-आटामऊ मार्ग पर सड़क किनारे दो युवकों के शव पड़े हैं। मृतकों की पहचान कछौना थाना क्षेत्र के रेसों निवासी अरुण चौरसिया और गौहनिया निवासी अभिषेक चौरसिया के रूप में हुई थी। दोनों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान मिले थे, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और क्षेत्राधिकारी संडीला की निगरानी में गठित टीमों ने जांच के दौरान कुलदीप और प्रमोद को गिरफ्तार किया, जबकि तीन बाल अपचारियों को

अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक अरुण एक बाल अपचारी की बहन से फोन पर बातचीत करता था और उससे मिलता-जुलता था। इसे लेकर आरोपी नाराज थे। कई बार समझाने के बावजूद बातचीत बंद न होने पर हत्या की साजिश रची गई। घटना से दो दिन पहले बांस काटकर डंडे तैयार किए गए और उन्हें घटनास्थल के पास छिपा दिया गया। 29 जुलाई की शाम अरुण और अभिषेक को कोल्ड ड्रिंक पार्टी के बहाने निमार्णाधीन पानी की टंकी पर बुलाया गया। वहां पहले से बनाई गई योजना के तहत दोनों पर बांस के डंडों, ईंट-पत्थरों से हमला किया गया।

पुलिस के अनुसार अरुण की सांस चलती देखकर उसके चेहरे पर तमंचे से गोली भी मारी गई, जिससे दोनों की मौत हो गई।पुलिस के मुताबिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि घटना से पहले आरोपियों ने मृतक अभिषेक से पूछा था कि हत्या के बाद पुलिस से कैसे बचा जा सकता है। इसके बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद न कर उन्हें अपने भाइयों के पास छोड़ दिया, ताकि उनकी लोकेशन दूसरे स्थान पर दिखाई देती रहे। वारदात के बाद दोनों मृतकों के मोबाइल भी अपने साथ ले गए।

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा, खोखा कारतूस, मृतकों के दो मोबाइल फोन, दो बांस के डंडे तथा घटनास्थल से चप्पल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और प्लास्टिक के गिलास बरामद किए हैं। मामले के सफल अनावरण में संडीला पुलिस के साथ एसओजी और सर्विलांस टीम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

विश्व स्तनपान सप्ताह - 2026 का प्राचार्य ने किया शुभारम्भ

वेब वार्ता, कानपुर। जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा आज विश्व स्तनपान सप्ताह - 2026 का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय काला उप-प्राचार्य डॉ. ऋचा गिरी एवं एस.आई.सी. डॉ. सौरभ अग्रवाल ,स्त्री रोग विभागध्यक्ष डॉ सीमा द्विवेदी व पूर्व विभागध्यक्ष डॉ रेनू गुप्ता द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व स्तनपान सप्ताह एवं विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्नातक (यूजी) एवं स्नातकोत्तर (पीजी) विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर स्तनपान के महत्व, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में इसकी भूमिका तथा समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।

कार्यक्रम में प्राचार्य की मौजूदगी में भावनात्मक रूप से विभागाध्यक्ष पद का औपचारिक कार्यभार हस्तांतरण समारोह भी किया गया। जिसमें प्रो. डॉ. रेनू गुप्ता ने प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष का कार्यभार प्रो. डॉ. सीमा द्विवेदी को सौंपा। इस अवसर पर सभी अतिथियों एवं विभागीय सदस्यों ने प्रो. डॉ. रेनू गुप्ता के सफल, दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके उल्लेखनीय योगदान को नमन किया तथा नव-नियुक्त विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. सीमा द्विवेदी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर विभाग की वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रो. डॉ. नीना गुप्ता, प्रो. डॉ. अनीता गौतम, प्रो. डॉ. शैली अग्रवाल, प्रो. डॉ. वंदना शर्मा तथा एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दिव्या द्विवेदी, डॉ. पविका लाल, डॉ. गरिमा गुप्ता, डॉ. दीपक आनंद, डॉ. प्रतिमा वर्मा, डॉ. उरूज जहाँ, डॉ. प्रीति त्यागी, डॉ. रश्मि गुप्ता, डॉ. रश्मि यादव एवं डॉ. करिश्मा शर्मा सहित विभाग के सभी शिक्षकगण, रेजिडेंट्स, इंटर्न एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

बालगृह और सम्प्रेक्षण गृह का जिला निरीक्षण समिति ने किया निरीक्षण

ललितपुर (आलोक चतुर्वेदी) जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को जिला निरीक्षण समिति ने राजकीय बालगृह (बालक), दैलवारा एवं राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, नेहरूनगर का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, सुरक्षा एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई।

निरीक्षण दल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट) नीरज कुमार महाजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवप्रिय सारस्वत, सिविल जज (जू. डि.) (एफटीसी) नवीन कुमार पांडे तथा एसडीएम ललितपुर हेमंत पटेल मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान सचिव देवप्रिय सारस्वत ने उच्च न्यायालय की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के निदेर्शों के अनुपालन में दोनों संस्थाओं में रह रहे बालकों एवं किशोरों से बातचीत कर उनकी शैक्षिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, भोजन, दैनिक दिनचर्या एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को भी गंभीरता से सुना।

समिति ने दोनों संस्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग व्यवस्था की भी जांच की। इस दौरान राजकीय बालगृह दैलवारा में केवल पिछले दो दिनों तथा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह नेहरूनगर में चार दिनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध मिली। इस पर सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिन से एक माह तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने सुनीं समस्याएं

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। तहसील सदर में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अनुनय झा ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, विद्युत, पंचायत, समाज कल्याण, सिंचाई सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जिन मामलों का मौके पर निस्तारण संभव है, उनका तत्काल समाधान किया जाए, जबकि अन्य मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शिकायतों का स्थलीय सत्यापन कर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। साथ ही लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर उनका शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी सदर, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

कुशीनगर: सिधरिया ड्रेन में डूबीं तीन मासूम बहनें, 12 घंटे बाद मिले शव

वेब वार्ता, कुशीनगर

कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के दुबौली गांव के समीप सिधरिया ड्रेन में शुक्रवार शाम हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार की तीन मासूम बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। करीब 12 घंटे तक चले तलाश अभियान के बाद शनिवार सुबह ग्रामीणों ने तीनों के शव बरामद किए। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार, दुबौली गांव निवासी शंभू की पुत्रियां सपना (10) और छोटी (8) तथा रंजीत की पुत्री कुंचन (12) शुक्रवार शाम खेत से घास काटकर घर लौट रही थीं। रास्ते में बभनौली गांव के समीप स्थित सिधरिया ड्रेन की पुलिया पर तीनों कुछ देर के लिए रुकीं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और तीनों पुलिया से नीचे तेज बहाव वाली ड्रेन में जा गिरीं। देखते ही देखते तीनों पानी की तेज धारा में समा गईं।

घटना के समय साथ मौजूद सपना का छोटा भाई कलुआ (10) शोर मचाते हुए गांव की ओर दौड़ा और ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण, मछुआरे और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए।

सूचना मिलने पर सदर एसडीएम राजीव निगम, तहसीलदार अभिषेक मिश्र, क्षेत्राधिकारी वीरेंद्र सिंह तथा सदर विधायक मनीष जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे। करीब तीन घंटे बाद एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थानीय पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से देर रात करीब एक बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद अभियान रोक दिया गया।

एक साथ तीन बेटियों की मौत से गांव में पसरा मातम

शव मिलने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घर पर चीख-पुकार मच गई और परिजनों को सांत्वना देने वालों का तांता लग गया। पुलिस ने तीनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार से मिलकर हरसंभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया।

शनिवार सुबह एनडीआरएफ टीम के पहुंचने से पहले ही दर्जनों ग्रामीण स्वयं ड्रेन में उतर गए और करीब एक घंटे की खोजबीन के बाद तीनों बच्चियों के शव बरामद कर लिए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की।

भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा फिर रुकी

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से नया जत्था नहीं हुआ रवाना

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर अमरनाथ यात्रियों की रफ्तार को रोक दिया है। खराब मौसम और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) के बंद होने के कारण शनिवार को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से श्रद्धालुओं का नया जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना नहीं किया जा सका। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई है।

जानकारी के अनुसार, करीब 250 किलोमीटर लंबा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन बंद रहा। उधमपुर जिले के लधा-समरोली क्षेत्र में सड़क की मरम्मत का कार्य चल रहा है। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से सड़क को हुए नुकसान के बाद शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा के काफिले के गुजरने के तुरंत बाद दोनों ओर से यातायात रोक दिया गया था। इसके बाद लगातार बारिश से सड़क पर कीचड़ जमा हो गया और मार्ग अत्यधिक फिसलन भरा हो गया, जिससे बहाली का कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

रामबन और उधमपुर जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी है।

अब तक 4.5 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बफार्नी के दर्शन

एनएच-44 कश्मीर घाटी को देश के शेष हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख ऑल वेदर मार्ग है। इसके बंद रहने से न केवल अमरनाथ यात्रा प्रभावित हुई है, बल्कि सामान्य यातायात पर भी असर पड़ा है। इस बीच, श्रद्धालुओं की संख्या में कमी को देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पंजीकरण और टोकन वितरण की व्यवस्था तवी रिवरफ्रंट से स्थानांतरित कर भगवती नगर आधार शिविर में कर दी है। पहले तवी रिवरफ्रंट पर ऑफलाइन पंजीकरण, टोकन वितरण, ई-केवाईसी सत्यापन और आरएफआईडी कार्ड जारी करने की केंद्रीकृत सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक लगभग 4.5 लाख श्रद्धालु दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। इससे पहले भी भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रा करीब छह दिनों तक स्थगित रही थी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मौसम और सड़क की स्थिति संबंधी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने की अपील की है। अमरनाथ यात्रा का समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होना निर्धारित है। फिलहाल यात्रा की आगे की व्यवस्था मौसम में सुधार और राष्ट्रीय राजमार्ग की बहाली पर निर्भर करेगी।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से मिले कई दिग्गज नेता

मुंबई। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके इन दिनों जबरदस्त राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में हैं। छत्रपति संभाजीनगर स्थित उनके आवास पर विभिन्न दलों के नेताओं, समाजसेवियों और कार्यकताओं के मिलने का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को अभिजीत दीपके से फोन पर बात की और उन्हें पूरे विपक्ष की ओर से एकजुट समर्थन देने का भरोसा दिलाया। यह बातचीत शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे के जरिए संभव हुई, जो व्यक्तिगत रूप से दीपके के घर पहुंचे थे। उन्होंने अभिजीत और उद्धव ठाकरे के बीच वीडियो कॉल करवाई। बातचीत के दौरान सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने साफ किया कि जब तक छात्रों की सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। फोन पर चर्चा के दौरान उद्धव ठाकरे ने अभिजीत और उनके माता-पिता को बांद्रा ईस्ट स्थित अपने आवास मातोश्री आने का न्योता भी दिया, जिसे दीपके ने सहर्ष स्वीकार करते हुए जल्द आने की बात कही।

मुस्लिम युवक ने 201 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठाई

मेरठ। श्रावण मास के पवित्र महीने में चारों ओर गूंजते हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष के बीच मेरठ के फलावदा कस्बे ने मजहब और सरहदों की दीवारों को पार कर सच्ची मानवता और सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण पेश किया है।

मोहल्ला होली चौक निवासी मंजूर के 22 वर्षीय बेटे शाकिर ने यह साबित कर दिया है कि निष्ठा और भक्ति किसी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती। अत्यंत गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले और मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले शाकिर का भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास बीते तीन वर्षों से लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष उसने हरिद्वार से 101 लीटर गंगाजल लाकर स्थानीय शिवालयों में जलाभिषेक किया था, वहीं इस वर्ष उसने 201 लीटर पवित्र गंगाजल की विशाल कांवड़ उठाई है।

सनातन परंपरा में महादेव को करुणा और समरसता का प्रतीक माना जाता है। शाकिर की यह कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का मजबूत संदेश दे रही है। हरिद्वार से लौटते समय रुड़की और अन्य पड़ावों पर स्थित कांवड़ सेवा शिविरों के कार्यकताओं और आम

भगवान शिव की भक्ति में डूबा शाकिर

श्रद्धालुओं ने शाकिर की इस अनूठी शिवभक्ति का जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे सम्मानित भी किया जा रहा है। इसी बीच, कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ के मवाना तहसील के बहादुरपुर गांव से सेवा और समर्पण की एक और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां के निवासी अमरपाल अपनी 81 वर्षीय मां ओमवती की मनोकामना पूरी करने के लिए उन्हें कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस अनोखी कांवड़ के एक तराजू में पवित्र गंगाजल और दूसरे में उनकी वृद्ध माता बैठी हैं।

इस पावन यात्रा में अमरपाल की बेटी साक्षी और पोता नैतिक भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। साक्षी ने बताया कि उनकी दादी की वर्षों से कांवड़ यात्रा करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन अत्यधिक उम्र और शारीरिक असमर्थता के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में पूरे परिवार ने उन्हें कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराने का निर्णय लिया। इस पर भावुक होकर ओमवती ने कहा कि ईश्वर की कृपा, बेटे की सेवा भावना और पोती के सहयोग से आज उनकी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी हो रही है। श्रद्धा, सौहार्द और मातृ-पितृ भक्ति के ये दृश्य इस बार की कांवड़ यात्रा को बेहद खास बना रहे हैं।

भारतीय मूल की बेटी की ईरानी मिसाइल से मौत

अमेरिका ने हीरो की तरह दी आखिरी विदाई

न्यूयॉर्क। ईरान युद्ध में शहीद हुई भारतीय मूल की अमेरिकी सेना की सर्जेंट एंजेल सारा रामप्रसाद को पूरे सैन्य सम्मान और भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ अंतिम विदाई दी गई। स्थानीय समयानुसार शुक्रवार को न्यूयॉर्क में उनके अंतिम संस्कार में अमेरिकी सेना के अधिकारी, सैनिक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।

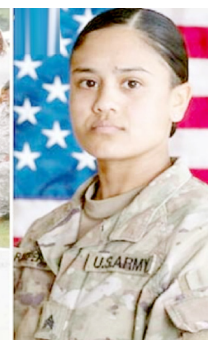

न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी भी शोक सभा में पहुंचे और सर्जेंट रामप्रसाद की बहादुरी तथा बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी सेवा और साहस को शहर हमेशा सम्मान के साथ याद रखेगा। शहादत के बाद न्यूयॉर्क राज्य में सम्मान स्वरूप सरकारी भवनों पर अमेरिकी झंडे आधे झुकाए गए। राज्य प्रशासन ने उनके सम्मान में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए। न्यूयॉर्क पुलिस के मोटरसाइकिल दस्ते की अगुवाई में उनके पार्थिव शरीर को चर्च तक ले जाया गया, जहां अंतिम प्रार्थना सभा आयोजित हुई। इसके बाद लॉन्ग आइलैंड स्थित कब्रिस्तान में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

एंजेल सारा रामप्रसाद की मां कैरोल एसेवेडो ने अपनी बेटी को एक सच्ची हीरो बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की सेवा को सर्वोपरि रखा। एंजेल का जन्म त्रिनिदाद में हुआ था और वह महज दो वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गई थीं। वहीं उनका पालन-पोषण हुआ और आगे चलकर उन्होंने अमेरिकी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा का मार्ग चुना।

डिफेंस कमांड के साथ थी तैनात

एंजेल सारा रामप्रसाद जर्मनी में आर्मी एयर एंड मिसाइल डिफेंस कमांड के साथ तैनात थीं। बाद में उन्हें जॉर्डन के मुवफ्फाक साल्टी एयर बेस पर भेजा गया, जहां जुलाई के मध्य में हुए ईरानी मिसाइल हमले में उनकी जान चली गई। उनके पार्थिव शरीर को 22 जुलाई को डोवर एयर फोर्स बेस लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। ईरान युद्ध में अब तक 18 अमेरिकी सैन्यकर्मियों की मौत हो चुकी है। एंजेल सारा रामप्रसाद के साथ कैप्टन टायलर जेम्स फीहान और प्राइवेट फर्स्ट क्लास इसाबेला गोंजालेस भी हमले में मारे गए थे। इसके अगले दिन इराक में ड्रोन हमले में सर्जेंट माइकल इमैनुएल स्विंटन की भी मृत्यु हो गई।

...जोड़कर देखा जा रहा है

शुरूआत में एंजेल और अन्य सैनिकों के नाम ईरान युद्ध में मारे गए सैन्यकर्मियों की सूची में शामिल किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें ओवरसीज ऑपरेशन्स श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया। इस बदलाव को लेकर अमेरिका में चर्चा तेज है और इसे युद्ध में हुई वास्तविक हताहतों के आंकड़ों से जोड़कर देखा जा रहा है।

कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में दूसरे मजदूर की भी मौत

जम्मू। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के कीलम इलाके में शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे दोनों की मौत हो गई। हमले के दौरान एक मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि दूसरे गंभीर रूप से घायल मजदूर को तुरंत बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, शनिवार को इलाज के दौरान दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें प्रारंभिक जांच में बताया गया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर निशाना बनाया था।

उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक को मंजूरी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आखिरकार उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त करने की आपसी सहमति को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों के बीच सभी विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान और आपसी सहमति के आधार पर लंबे समय से चले आ रहे मामले का निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति पीएस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, उमर और पायल दोनों ने अदालत को सूचित किया कि उनके बीच लंबित सभी विवाद सुलझ गए हैं और वे वैवाहिक संबंध समाप्त करने पर सहमत हैं।

स्पेन में घुस रहे हड़बड़ी के चलते समुद्र में गिरे अब तक 57 की मौत

स्यूटा। उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र स्यूटा की सीमा पर प्रवासियों के एक विशाल समूह के जबरन दाखिल होने की कोशिश के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। गुरुवार और शुक्रवार के बीच मोरक्को की ओर से लगभग 60 हजार प्रवासी स्पेनिश क्षेत्र स्यूटा में प्रवेश कर गए, जो इस शहर की कुल आबादी के करीब 70 प्रतिशत के बराबर है। इस अचानक हुए बड़े पैमाने पर प्रवास के दौरान मची भगदड़ और समुद्र में डूबने के कारण कम से कम 57 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बिगड़ती स्थिति पर काबू पाने के लिए स्पेनिश अधिकारियों को सीमा पर सेना की तैनाती करनी पड़ी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई वैश्विक

नेताओं ने इस दुखद घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है।

स्यूटा को अक्सर अफ्रीका से यूरोप में प्रवेश करने का मुख्य द्वार माना जाता है। सीमा पार करने के लिए प्रवासियों ने तराजल ब्रेकवाटर के पास समुद्र में तैरकर, टायरों और रबर ट्यूबों के सहारे तथा कंटीले तारों की बाड़ को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान सीमा पर मोरक्को के सुरक्षा बलों और प्रवासियों के बीच भीषण झड़पें हुईं। भीड़ को नियंत्रित करने और तितर-बितर करने के लिए मोरक्कन बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, हवा में गोलियां चलाईं और कई वाहनों में भी आग लगा दी गई। हालांकि, देर शाम तक सुरक्षा बलों के कड़े रुख के बाद लगभग 37 हजार प्रवासी वापस मोरक्को की ओर लौट गए। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने स्यूटा का दौरा किया और इस सीमा उल्लंघन को स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा हमला करार दिया।

पुजारी के वेश में प्रदर्शन पर पप्पू यादव के खिलाफ थाने में शिकायत

नई दिल्ली। संसद परिसर में राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा घोटाले के मुद्दे पर पुजारी के वेश में प्रदर्शन करने वाले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

शिकायतकर्ता सूर्य मैथिल ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया गया, जिससे सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने संबंधित नेताओं के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, संसद के बाहर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर मंदिर के पुजारी के रूप में प्रदर्शन कर रहे थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस दौरान भगवान राम लला की तस्वीर का अनुचित तरीके से उपयोग किया गया और धार्मिक प्रतीकों का अपमान हुआ। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस प्रदर्शन को विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई सांसदों का समर्थन प्राप्त था। सूर्य मैथिल ने गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस आयुक्त, संबंधित डीसीपी, एसीपी और जहांगीरपुरी थाना प्रभारी को संबोधित शिकायत में मांग की है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पप्पू यादव और प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल, शुक्रवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप

नेपाल के चार सीमावर्ती जिलों में हिंसा, 3 की मौत कई घायल

अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू, पीएम शाह ने संभाला मोर्चा

काठमांडु। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में धार्मिक विवाद को लेकर भड़का तनाव अब हिंसक रूप ले चुका है। दक्षिण तेराई और मधेश क्षेत्र के जिलों में बिगड़ती स्थिति को देखतेहुएप्रशासनने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। ताजा आदेशों के बाद अब भारत की सीमा से लगे चार प्रमुख जिलों–सप्तारी, सुनसारी, धानुषा और सिराहा–में कड़ी पाबंदियां लागू हैं।

हिंसा की शुरूआत सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका अंतर्गत कप्तानगंज इलाके में हुई थी, जहां रविवार को एक उत्सव के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि सुरक्षाकर्मियों समेत एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इसके बाद यह हिंसा आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई। सिराहा जिले में एक किशोर की जान चली गई, वहीं सुनसारी हिंसा में घायल एक अन्य व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो

गई। इस प्रकार अब तक इस हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। एक अन्य घटना में पुलिस कॉन्स्टेबल नारद पेरियार को भी गोली लगी है।

तनाव की यह आग गोलबाजार क्षेत्र से होती हुई लहान नगरपालिका तक पहुंच गई है। उपद्रवियों ने कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन किए और गोलबाजार इलाके में स्थित एक शॉपिंग मॉल को आग के हवाले कर दिया। बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को मुस्तैद किया गया है और प्रभावित इलाकों में लोगों की आवाजाही पर सख्त रोक लगा दी गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और जनता से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हालिया हिंसा की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराएगी तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने स्थिति का सर्वसम्मति से समाधान निकालने के लिए काठमांडू में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। साथ ही, उन्होंने नागरिकों से विशेष आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाहें, गलत जानकारी या नफरत फैलाने वाली सामग्रियां साझा न करें। फिलहाल पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।

अमेरिका का एफ-35बी स्टील्थ फाइटर क्रैश, पायलट सुरक्षित

कैलिफोर्निया। अमेरिका का एडवांस्ड एफ-35बी लाइटनिंग-2 स्टील्थ लड़ाकू विमान गुरुवार को कैलिफोर्निया के मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मिरामार में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब हाल ही में ईरान ने 3 एफ-35 को तबाह करने का दावा किया था, हालांकि इस क्रैश का ईरान से कोई संबंध नहीं है और न ही यह पश्चिम एशिया में हुआ है। स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10 बजे यह विमान रनवे के पास गिरा और दो बड़े हिस्सों में टूटकर उसमें आग लग गई। राहत की बात यह रही कि पायलट समय रहते इजेक्ट करने में सफल रहा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई है। मरीन कॉर्प्स ने पुष्टि की कि यह विमान मरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप-11 और थर्ड मरीन एयरक्राफ्ट विंग का हिस्सा था। शुरूआती जानकारी के मुताबिक, विमान रनवे तक पहुंचने से पहले ही नीचे आ गया। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। एफ-35बी, अमेरिका के एफ-35 लाइटनिंग-2 फैमिली का एक विशेष जेट है, जिसे शॉर्ट टेकऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग क्षमता के साथ तैयार किया गया है।

चांद पर गिरने वाला है 4500 किलो का अनियंत्रित स्पेसएक्स रॉकेट

वॉशिंगटन। अंतरिक्ष में छोड़े गए हर रॉकेट का सफर उसके मिशन के साथ खत्म नहीं होता, कई बार उसका एक हिस्सा वर्षों तक बिना किसी नियंत्रण के अंतरिक्ष में भटकता रहता है। अब ऐसा ही एक स्पेसएक्स रॉकेट का ऊपरी हिस्सा (अपर स्टेज) बुधवार, 5 अगस्त को चंद्रमा से टकराने वाला है। यह कोई योजनाबद्ध मिशन नहीं है, बल्कि एक अनियोजित टक्कर है, जिसने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है और भविष्य के चंद्रमा से जुड़े मिशनों को लेकर नई चिंताएँ पैदा की हैं।

अंतरिक्ष ट्रैकिंग विशेषज्ञ बिल ग्रे के अनुसार, यह रॉकेट का हिस्सा लगभग 8,700 किलोमीटर प्रति घंटा (5,400 मील प्रति घंटा) की रफ्तार से चंद्रमा के आइंस्टीन क्रेटर के पास टकराएगा। टक्कर इतनी तेज होगी कि इसकी ऊर्जा करीब तीन टन टीएनटी के विस्फोट के बराबर मानी जा रही है। यह घटना दशकों से बढ़ते अंतरिक्ष मलबे की समस्या को उजागर करती है। यह रॉकेट स्टेज 15 जनवरी 2025 को दो निजी चंद्रमा मिशनों को लेकर लॉन्च हुआ था। इनमें फायरफ्लाई एयरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर सफलतापूर्वक चांद पर उतर गया था, जबकि जापान की कंपनी

आईस्पेस का लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मिशन पूरा होने के बाद, रॉकेट के इस हिस्से को किसी सुरक्षित कक्षा या सूर्य की परिक्रमा वाली कक्षा में भेजा जा सकता था, ताकि यह अंतरिक्ष में अनावश्यक कचरा न बने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यह लगभग डेढ़ साल तक अंतरिक्ष में अनियंत्रित तरीके से घूमता रहा। अब इसकी कक्षा चंद्रमा से टकराने की स्थिति में पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दुर्घटना स्पेसएक्स की योजना का हिस्सा नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष में बढ़ते अनियंत्रित मलबे का सीधा नतीजा है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस एक टक्कर से फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन यह घटना एक बड़ी और गंभीर समस्या की ओर स्पष्ट इशारा करती है। स्पेस ट्रैकिंग विशेषज्ञ बिल ग्रे कहते हैं, अंतरिक्ष अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा भीड़भाड़ वाला हो गया है। एक वैज्ञानिक बेंजामिन फर्नांडो का भी कहना है कि अभी यह टक्कर तत्काल चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जब भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के स्थायी बेस बनाए जाएंगे, तब इस तरह का अनियंत्रित स्पेस जंक एक बड़ा खतरा बन सकता है। उनके मुताबिक, इस घटना का गहन अध्ययन करना बेहद जरूरी है ताकि यह समझा जा सके कि भविष्य में ऐसे टकराव अंतरिक्ष यात्रियों और चंद्रमा के ठिकानों के लिए कितने जोखिम भरे हो सकते हैं। यह घटना अंतरिक्ष में कचरे के प्रबंधन और नियंत्रण की आवश्यकता को फिर से रेखांकित करती है।

ताजा खबर
संक्षिप्त

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर तथा वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार बीजापुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं। इसी क्रम में कलेक्टर विश्वदीप ने शुक्रवार को भोपालपटनम क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का व्यापक दौरा कर राहत कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने सबसे पहले इंद्रावती नदी के तिमेड़ पुल का निरीक्षण कर जलस्तर और आवागमन की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद वे चंदनगिरी राहत शिविर पहुंचे और वहां रह रहे बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। राहत शिविर में भोजन, स्वच्छ पेयजल, कपड़े, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत शिविर में रह रहे सभी परिवारों को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए। उन्होंने बाढ़ से हुई क्षति का शीघ्र सर्वे कर पात्र प्रभावित परिवारों को शासन के नियमानुसार मुआवजा और अन्य राहत सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए।

धमतरी को मिली 7.32 करोड़ रुपए की सौगात:122 ग्राम पंचायतों में बनेंगे आधुनिक मुक्तिधाम शेड

रायपुर. आधुनिक मुक्तिधाम शेड अंतिम संस्कार स्थलों पर धूप और बारिश से बचाव के लिए बनाए जाने वाले पक्के और व्यवस्थित ढांचे हैं, जिन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा इन स्थलों पर शेड, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का स्थायी समाधान करते हुए धमतरी जिला प्रशासन ने एक संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण पहल की है।

बस्तर के लिए अरुणाचल मॉडल पर जोर: पीएम सड़क योजना में 10 किमी क्लस्टर की मांग

नई दिल्ली। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर के दूरस्थ और दुर्गम गांवों तक सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर के लिए अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर 10 किलोमीटर क्लस्टर मॉडल लागू करने की मांग रखी। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी मौजूद रहे। सीएम साय ने कहा कि बस्तर के कई गांव घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत केवल 500 मीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाता है, जिससे अनेक छोटे और दूरस्थ गांव सड़क सुविधा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि बस्तर में भी 10 किलोमीटर की परिधि वाले क्लस्टर की विशेष अनुमति दी जाए, ताकि अधिक गांवों को सड़क संपर्क मिल सके। सीएम ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से निकलकर विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

बस्तर के प्रतिनिधियों ने देखा राष्ट्रपति भवन, बस्तर की संस्कृति का हुआ भव्य सम्मान

रायपुर. राष्ट्रपति भवन में बस्तर के प्रतिनिधिमंडल के लिए एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक क्षण साकार हुआ। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर से पहुंचे परगना मांझियों, चालकियों, बस्तर पंडुम के जनजातीय कलाकारों तथा समाज प्रतिनिधियों का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने सभी अतिथियों का शॉल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मान किया और बस्तर की समृद्ध जनजातीय परंपरा एवं संस्कृति के प्रति अपना विशेष स्नेह व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन और पहल से आयोजित इस विशेष यात्रा ने बस्तर के जनजातीय समाज को देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रपति भवन में बस्तर की संस्कृति का जो सम्मान हुआ, उसने प्रतिनिधिमंडल के प्रत्येक सदस्य को गौरव और आत्मविश्वास से भर दिया। प्रतिनिधिमंडल के लिए सबसे भावुक और प्रेरणादायी क्षण उस समय आया, जब राष्ट्रपति महोदया ने एक आत्मीय मेजबान की भूमिका निभाते हुए स्वयं अपने हाथों से सभी अतिथियों को भोजन परोसा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रतिनिधियों को दाल परोसी, जबकि उप मुख्यमत्री श्री विजय शर्मा और सस्कृति मत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सभी को मिठाई परोसकर उनका स्वागत-सत्कार किया। राष्ट्रपति भवन में आत्मीयता और अपनत्व से भरे इस दृश्य ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को भावविभोर कर दिया। बस्तर से आए जनजातीय प्रतिनिधियों ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। इस अवसर पर एक और ऐतिहासिक पल तब आया, जब बस्तर पंडुम के विजेता कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन परिसर में अपनी पारंपरिक लोकगीत और लोकनृत्य की प्रस्तुति दी। बस्तर की लोक संस्कृति, वेशभूषा और पारंपरिक कला का यह अनुपम प्रदर्शन उपस्थित सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना और राष्ट्रपति भवन पहली बार बस्तर का सास्कृतिक रगत स सराबार हो उठा। माहौल ऐसा हुआ कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह, पूर्व बस्तर आईजी सुंदरराज पी और सभी अधिकारी भी लोकनृत्य में झूमने लगे। राष्ट्रपति महोदया से बात करते हुए कांकेर के पद्म सम्मान से अलंकृत काष्ठ कलाकार श्री अजय मंडावी ने कहा कि बस्तर की कला और संस्कृति विश्व में अद्वितीय है। लंबे समय तक भय और असुरक्षा के वातावरण के कारण इस विरासत को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि अब सुरक्षा बलों के साहस और सरकार के प्रयासों से बस्तर में शांति का वातावरण स्थापित हुआ है।

577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री ने जताया केंद्र सरकार का आभार

2,305 नए मोबाइल टावरों के लिए मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से मांगी मंजूरी

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में डिजिटल एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से प्रदेश के दूरस्थ, जनजातीय, सीमावर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों में निर्बाध मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 2,305 नए मोबाइल टावरों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भौगोलिक दृष्टि से कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी आज केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मोबाइल नेटवर्क और हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता से इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तक सहज पहुंच मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के अनेक दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संचार नेटवर्क का विस्तार चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे क्षेत्रों में 2,305 नए मोबाइल टावरों की स्थापना डिजिटल समावेशन की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उन गांवों और बसाहटों तक भी विश्वसनीय मोबाइल एवं इंटरनेट नेटवर्क पहुंचेगा, जो अब तक पर्याप्त संचार सुविधाओं से वंचित रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित रहे एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर केंद्र सरकार तथा केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से बस्तर सहित कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में आज शांति और विकास का नया वातावरण बन रहा है, वहां मजबूत संचार नेटवर्क विकास की गति को और तेज करेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद मजबूत होगा, आपातकालीन परिस्थितियों में संपर्क सुगम होगा और शासन की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लोगों को अपने गांव के निकट ही प्राप्त हो सकेगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार स्वीकृत मोबाइल टावरों की स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। कुल 577 स्थानों में से अब तक 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किए जा चुके हैं। शेष 88 स्थानों के लिए भी आवश्यक प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है और शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर आवश्यक अनुमति और भूमि संबंधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां बीएसएनएल द्वारा मोबाइल टावरों की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य शासन संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के माध्यम से आवश्यक समन्वय सुनिश्चित कर रहा है, ताकि टावरों की स्थापना में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो।

बस्तर के 461 पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों तक बिजली पहुंचाने की पहल

मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री से की मुलाकात

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत बस्तर संभाग के 7 जिलों के 461 दूरस्थ और पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों तक ग्रिड बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से 435 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सौंपते हुए कहा कि जिन गांवों में वर्षों तक नक्सल हिंसा के कारण विकास नहीं पहुंच सका, वहां अब बिजली जैसी बुनियादी सुविधा पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 973 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र सरकार से तीन वित्तीय वर्षों में सहायता मांगी गई है। वर्ष 2026-27 में 85 करोड़ रुपये, 2027-28 में 250 करोड़ रुपये और 2028-29 में 100 करोड़ रुपये, यानी कुल 435 करोड़ रुपये केंद्र से अपेक्षित हैं, जबकि शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत इस प्रस्ताव को विशेष प्रकरण मानते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि बस्तर के दूर-दराज़ गांव भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि बिजली पहुंचने से आदिवासी परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा छोटे उद्योगों को नई गति मिलेगी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत प्रस्ताव प्राप्त होते ही उस पर तत्काल स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए धनराशि की कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।

रायपुर प्रेस क्लब खेल मड़ई-2026 का पारितोषिक वितरण समारोह 2 अगस्त को

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक खेल महोत्सव खेल मड़ई-2026 का पारितोषिक वितरण समारोह 2 अगस्त को मधुकर खेर स्मृति प्रेस क्लब भवन में आयोजित किया जाएगा। समारोह में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेता, उपविजेता एवं दोनों सेमीफाइनलिस्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि रायपुर प्रेस क्लब के वार्षिक खेल महोत्सव खेल मड़ई-2026 के अंतर्गत इंटर प्रेस क्रिकेट प्रतियोगिता के अलावा शतरंज, बैडमिंटन, कैरम एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। इसके साथ ही महिला पत्रकारों की क्रिकेट टीमों के बीच एक प्रदर्शन मैच तथा संपादकों की टीमों के बीच भी मैत्री मुकाबला खेला गया। पूरे आयोजन में लगभग 300 खिलाड़ियों एवं पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। वरिष्ठ पत्रकार स्व. कुलदीप निगम स्मृति इंटर प्रेस क्रिकेट प्रतियोगिता में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। नेताजी सुभाष स्टेडियम में खेले गए मुकाबलों में इलेक्ट्रॉनिक संयुक्त (कप्तान- मोहन तिवारी) ने विजेता बनने का गौरव हासिल किया, जबकि विस्तार न्यूज इलेवन (कप्तान- ज्ञानेन्द्र तिवारी) उपविजेता रही। आईबीसी-24 (कप्तान- रामेश्वर मिश्रा) एवं एस जर्नो (कप्तान- लविन्दर सिंह) की टीमें सेमीफाइनलिस्ट रहीं। वरिष्ठ पत्रकार स्व. देवेन्द्र कर स्मृति बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनियन क्लब में आयोजित हुई। एकल वर्ग में रामेश्वर मिश्रा विजेता एवं चंदन साहू उपविजेता रहे, जबकि सत्येंद्र कर और सुशील अग्रवाल सेमीफाइनलिस्ट रहे। युगल वर्ग में सत्येंद्र कर-टीकम साहू की जोड़ी विजेता तथा चंदन साहू-सुशील अग्रवाल की जोड़ी उपविजेता रही। टिकेश्वर पटेल-अभिषेक तथा शुभम वर्मा-अमित मिश्रा की जोड़ियां सेमीफाइनलिस्ट रहीं। वरिष्ठ पत्रकार स्व. सत्येंद्र गुमाश्ता स्मृति टेबल टेनिस प्रतियोगिता के एकल वर्ग में विनोद कुमार विजेता और हितेश मेहता उपविजेता रहे। विजय मिश्रा एवं सिद्धांत सेमीफाइनलिस्ट रहे। युगल वर्ग में विनोद कुमार-विजय मिश्रा की जोड़ी विजेता तथा लक्ष्मण लेखवानी-हितेश मेहता की जोड़ी उपविजेता रही।

पूर्व में हुई खेल स्पर्धा के विजेता-उपविजेता भी होंगे पुरस्कृत

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मड़ई 2026 के 2 अगस्त को पारितोषिक वितरण समारोह में पूर्व में (2020 - 21) संपन्न खेल स्पर्धा के विजेता और उपविजेता भी पुरस्कृत होंगे। 2020 - 21 में आयोजित टेबल टेनिस , कैरम , शतरंज और बैडमिंटन प्रतियोगिता के खिताब विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों के आग्रह पर उन्हें भी 2 अगस्त के समारोह में पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है । शतरंज का खिताब संदीप तिवारी ने जीता था और गुड्डु बैरागी उपविजेता थे । बैडमिंटन एकल में सत्येंद्र कर विजेता एवं चंदन साहू उपविजेता थे । डबल्स में चंदन साहू और सुशील अग्रवाल की जोड़ी विजेता बनी थी व सत्येंद्र कर विजय मिश्रा की जोड़ी उपविजेता रही ।

7 अगस्त को रायपुर में लगेगा जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर

विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम करेगी नि:शुल्क जांच और उपचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम नागरिकों को आयुष चिकित्सा पद्धति का लाभ पहुंचाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जिला आयुर्वेद अधिकारी रायपुर के मार्गदर्शन में आयोजित होगा, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी के विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क उपचार और दवाइयों का वितरण करेंगे। यह स्वास्थ्य शिविर प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक सांस्कृतिक भवन, डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड क्रमांक-68, चंगोराभाठा, रायपुर में आयोजित किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत संचालित योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना तथा लोगों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूक करना है। शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा रोगों का निदान, उपचार संबंधी परामर्श, जीवनशैली में सुधार के सुझाव तथा आवश्यकतानुसार निःशुल्क औषधियों का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे मरीजों को आवश्यक जांच के लिए अलग से भटकना नहीं पड़ेगा। आयोजन में आयुष कार्ड के निर्माण एवं वितरण की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं, स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, दंत रोग सहित अन्य सामान्य बीमारियों की जांच एवं उपचार की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा लोगों को रोगों की रोकथाम और बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए आवश्यक परामर्श दिया जाएगा। शिविर में लाइव योग सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, जोड़ों के दर्द, मोटापा, तनाव, अनिद्रा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रभावी योग अभ्यास और प्राकृतिक उपायों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही घरेलू जड़ी-बूटियों एवं आयुष आधारित जीवनशैली से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे लोगों को पारंपरिक उपचार पद्धतियों की उपयोगिता समझने का अवसर मिलेगा। विशेष आकर्षण के रूप में बालको कैंसर अस्पताल, नया रायपुर की टीम द्वारा कैंसर से संबंधित जांच एवं परामर्श दिया जाएगा। वहीं एम.जी.एम. नेत्र संस्थान, रायपुर के विशेषज्ञों द्वारा नेत्र रोगों की जांच, परामर्श तथा जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क चश्मों का वितरण भी किया जाएगा। आयोजकों ने शिविर में आने वाले सभी मरीजों से अपील की है कि वे अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट एवं डॉक्टर की पर्चियां साथ लेकर आएं, ताकि विशेषज्ञ चिकित्सक उनकी स्वास्थ्य स्थिति का बेहतर मूल्यांकन कर उचित उपचार उपलब्ध करा सकें। जिला आयुष विभाग ने आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में इस स्वास्थ्य शिविर में भाग लेकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है।

कृषि मंत्री नेताम ने कहा: 472 जगहों पर हुई कार्रवाई,

खाद की कालाबाजारी पर सख्ती: 68 हजार बोरी खाद जब्त, 11 लोगों पर एफआईआर

रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कांफ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, खाद की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरे प्रदेश में अब तक 472 जगहों पर कार्रवाई की गई है। 68 हजार बोरी फ़र्टिलाइजर खाद कृषि विभाग ने जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान 11 दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसके अलावा 11 लोगों पर स्न्ढ्ढक्र भी दर्ज किया गया है। मंत्री नेताम ने कहा, बस्तर आज शांति का टापू बना है, बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन मत्स्यपालन इन विभागों के सामूहिक प्रयासों से उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता है। सभी डायरेक्टर और संचालकों ने बस्तर का दौरा किया। जिन क्षेत्रों में काम हो रहा वहां जाकर देखा, जो हितग्राही, किसान जुड़े हैं, उनसे बात की गई। हमने निर्णय लिया है कि उन क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने का काम होगा, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। एक छत के नीचे सभी विभागों को एक साथ ट्रेनिंग देने की योजना बनाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा, धान और केले की फसल में सर्वाधिक पानी की जरूरत होती है। इन फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। हम अधिकारियों के माध्यम से कृषि संकल्प अभियान चलाकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मियों में धान के बदले दलहन, तिलहन या सब्जी की खेती करते हैं तो पानी की जरूरत कम पड़ेगी। जैविक उत्पादन बढ़ाने, धान के बदले दलहन, तिलहन, फूलों की खेती कर कैसे आगे बढ़ें, इस पर फोकस हैं। उन्होंने कहा, कोशिश यह भी है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो, उसकी तुलना में जैविक खाद की दिशा में कैसे आगे बढ़ें, इस पर फोकस है। कम वर्षा में कैसे खेती करें इस पर विभाग फोकस कर रहा है। जल की उपलब्धता हो, इसके लिए कोरबा के बांगो डैम को चिन्हांकित किया गया है।मंत्री नेताम ने कहा, पीएम आशा योजना के तहत प्रदेश में पहली बार दलहन तिलहन फसल की खरीदी की गई। एमएसपी के आधार पर खरीदी हो तो किसानों को डर नहीं होता कि वो फसल उगाये या नहीं, लेकिन इस बार खरीदी की व्यवस्था है। आगे चलकर इस योजना पर और भी विस्तार होगा। उन्होंने कहा, किसानों के हित में कोई भी बाधा डालने का प्रयास करेगा उस पर विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा।

मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि किसी ने सही हाइब्रिड और अमानक बीजों को लेकर लापरवाही की, किसानों को गलत बीज और गलत खाद का वितरण हुआ तो विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।विभागीय सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने विभाग के कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, प्रदेश में लगभग 40 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें 82त्न लघु एवं सीमांत किसान हैं। 30 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 543.4 मिमी औसत वर्षा हुई, जो 10 वर्षों के औसत से अधिक है। खरीफ 2026 में 48.69 लाख हेक्टेयर बोनी का लक्ष्य है, अब तक 83 प्रतिशत बोनी हो चुकी है।

कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की मौत पर सीएम साय ने जताया शोक

रायपुर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार शाम हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी श्रमिकों की मौत होने पर सीएम साय ने शोक व्यक्त किया है। आतंकियों ने केलम क्षेत्र स्थित एक ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। हमले में 24 वर्षीय दीपक रात्रे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 28 वर्षीय भूपेंद्र कुमार ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में मृतक श्रमिक को श्रद्धांजलि दी और प्रारंभिक जानकारी के आधार पर घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। बाद में इलाज के दौरान दूसरे श्रमिक की भी मौत की पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक सहायता और समन्वय के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने देर शाम ईंट-भट्ठे पर अचानक गोलीबारी की, जिससे वहां काम कर रहे प्रवासी मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। घायल भूपेंद्र कुमार को पहले जीएमसी अनंतनाग और बाद में श्रीनगर के एसकेआईएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने सोशल मीडिया पर ली है। समूह ने बाहरी लोगों और जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने की धमकी भी दी है।

रियल मैड्रिड ने युवा स्ट्राइकर कार्लोस को अपने साथ जोड़ा

मैड्रिड। स्पेन के शीर्ष फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने लेवांते के युवा स्ट्राइकर कार्लोस एस्पी को अपने साथ जोड़ा है। रियल मैड्रिड ने एस्पी को करीब 25 मिलियन यूरो की मोटी रकम देकर खरीदा है। ऐसे में अब अगल सत्र से कार्लोस रियल की ओर से खेलते हुए दिखेंगे। रियल ने कहा कि कि कार्लोस अगले पांच साल तक उसके पास ही रहेंगे। इसके तहत ये फुटबॉलर जून, 2031 तक रियल की ओर से खेलेगा।

गौरतलब है कि रियल मैड्रिड में आने से पहले कार्लोस ने लेवांते की ओर से तीन सत्र खेले हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 66 मैचों में 20 गोल दागे हैं। उनका पिछला सीजन विशेष रूप से अच्छा रहा। इस दौरान उन्होंने 27 मैचों में 13 गोल किये। उन्हें पिछले सीजन में लीग का सर्वश्रेष्ठ अंडर-23 खिलाड़ी भी चुना गया था। कार्लोस के इन गोलों के कारण ही लेवांते को निचली लीग में जाने से बचा था। सत्र सीजन के आखिरी हफ्तों में उनके प्रदर्शन ने टीम को मजबूती मिली थी।

इस स्ट्राइकर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए स्पेनिश ला लीगा के क्लब विल्लारियल और इंग्लैंड की प्रीमियर लीग के साथ ही कई बड़े क्लबों ने भी रुचि दिखायी थी। रियल मैड्रिड ने हालांकि इस दौड़ में बाजी मार ली। लेवांते ने संभावित चोट के खतरे को कम करने के लिए प्री-सत्र फ्रेंडली मैचों से बाहर रखा था, जो आमतौर पर बड़े ट्रांसफर से पहले किया जाता है।

कार्लोस का रियल मैड्रिड में ऐसे समय में आये जब क्लब अपने स्ट्राइकर गोंजालो गार्सिया को इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब फुलहम को बेचने के करीब पहुंच गया है। गोंजालो की यह डील लगभग 40 मिलियन यूरो में फाइनल होने वाली है, जिससे मैड्रिड को काफी रकम मिलेगी। इससे टीम में नए स्ट्राइकर को भी जगह मिलेगी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कार्लोस को अगले सत्र में सीधे मैड्रिड की फर्स्ट-टीम स्क्वाड में शामिल किया जाएगा या उन्हें शीर्ष स्तर का अनुभव हासिल करने के लिए किसी अन्य क्लब में लोन पर भेजा जाएगा। यह निर्णय शायद उनके प्री-सीजन प्रदर्शन और क्लब की रणनीतिक जरूरतों पर निर्भर करेगा।

वैभव को कम उम्र में उपकप्तानी दिये से एक नई बहस शुरू हुई

दिग्गज खिलाड़ियों ने जतायी चिंता , चयनकर्ता ने किया बचाव

मुम्बई। 15 साल के उभरते हुए क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को अगले माह होने वाले दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाये जाने के बाद से ही एक नई बहस शुरू हो गयी है। कई दिग्गजों का कहना है कि इतनी कम उम्र में अपकप्तानी के बोझ से वैभव का खेल प्रभावित होगा। वहीं चयनकताओं ने अपने कदम को सही करार देते हुए वैभव को भविष्य का कप्तान करार दिया।

खेल विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों के एक वर्ग ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वैभव पर उप-कप्तानी का अतिरिक्त दबाव डालने की जगह उन्हें अपनी बल्लेबाजी और खेल पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए थी। विशेषज्ञों का मानना है कि एक उभरते हुए सितारे पर इतनी जल्दी नेतृत्व की भूमिका थोपना उसकी प्राकृतिक प्रगति में बाधा डाल सकता है।

हालांकि, आलोचनाओं के इस माहौल के बीच ईस्ट जोन के चयनकताओं में से एक और पूर्व रणजी खिलाड़ी प्रबंजन मलिक ने इस फैसले का बचाव किया। मलिक ने चयन समिति के इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे की सोच को स्पष्ट किया। मलिक ने उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए जोर देकर कहा कि वैभव को कप्तान नहीं, बल्कि उप-

कप्तान बनाया गया है, कप्तानी की जिम्मेदारी अनुभवी ईशान किशन निभाएंगे।

मलिक ने समझाया, ईशान एक विकेटकीपर हैं जो मैदान पर पूरे दिन सक्रिय रहते हैं और खेल की रणनीतियों में शामिल होते हैं। मलिक ने आगे कहा कि जैसे-जैसे वैभव परिपक्व हो रहे हैं, उन्हें अधिक जिम्मेदारी देने से वह एक खिलाड़ी और नेतृत्वकर्ता के रूप में और बेहतर बनकर उभरेंगे। चयनकताओं का मानना है कि वैभव के लिए नेतृत्व की यह भूमिका नई नहीं है। मलिक ने याद दिलाया कि वह अपनी घरेलू टीम बिहार के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी उप-कप्तान की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 2026 के अंडर-19 विश्व कप में भी वह भारतीय टीम में आयुष म्हात्रे के डिप्टी (उप-कप्तान) रह चुके हैं।

वैभव के हालिया प्रदर्शन की तारीफ करते हुए मलिक ने कहा, वह देश के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और राजस्थान रॉयल्स के लिए उनका हालिया आईपीएल सीजन भी बेहद शानदार रहा है। दलीप ट्रॉफी जैसे बड़े मंच पर यह जिम्मेदारी उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है। वह देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं और चयनकताओं के रूप में हमारा मानना है कि युवा खिलाड़ियों को जिम्मेदारी देना बहुत जरूरी है। मलिक ने यह भी संकेत दिया कि चयनकर्ता वैभव में भविष्य के भारतीय कप्तान की झलक देखते हैं। उन्होंने कहा, कौन जानता है? हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन वह भारतीय नेशनल टीम के कप्तान भी बन सकते हैं।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए फिट हुए बुमराह

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब अगले माह श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में खेल सकेंगे। बुमराह के रास्ते में आयी अड़चन दूर हो गयी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ अगले महीने होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में खेलने की अनुमति दे दी है। बुमराह को पूरी तरह से फिट होने के कारण ये अनुमति मिली है। इंग्लैंड के खिलाफ हाल में एकदिवसीय सीरीज के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। इस चोट के कारण ही वह अंतिम एकदिवसीय से बाहर थे। इसी कारण उनके श्रीलंक के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने को लेकर भी आशंकाएं व्याप्त थीं।

बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, बुमराह अपनी चोट से उबर चुके हैं। उन्होंने जरूरी फिटनेस टेस्ट

पास कर लिए हैं। उम्मीद है कि वह सीरीज के दोनों मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे क्योंकि वह टीम की योजनाओं का अहम हिस्सा हैं। श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त को गाले में शुरू होगी और दूसरा मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा होने के कारण भारतीय टीम के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय टीम को अपने बचे हुए 9 टेस्ट मैचों में से 7 जीतने होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ विदेशी धरती पर होने वाली सीरीज से पहले भारतीय टीम को दौड़ में बने रहने के लिए श्रीलंका के खिलाफ सीरीज को 2-0 से जीतना होगा क्योंकि न्यूजीलैंड का दौरा कठिन रहने वाला है। भारतीय टीम पहले से ही तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नितीश रेड्डी के उपलबध्ध नहीं होने से मुश्किल में है। ऐसे में बुमराह जैसे मुख्य गेंदबाज के फिट होने से भारतीय टीम प्रबंधन को राहत मिली है।

श्रीलंका दौरे में क्लीन स्वीप कर इतिहास दोहराना चाहेगी भारतीय क्रिकेट टीम

मुम्बई। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम अगले माह 15 अगस्त से मेजबान श्रीलंकाई टीम के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए उतरेगी। भारतीय टीम का लक्ष्य दो मैचों की इस सीरीज को जीतकर इतिहास दोहराना रहेगा। श्रीलंका की धरती पर भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट रिकॉर्ड काफी रोमांचक रहा है। भारत ने अब तक वहां कुल आठ टेस्ट सीरीज खेली हैं, जिनमें से तीन बार सीरीज उसने

जीती है जबकि तीन बार मेजबान श्रीलंका की टीम को जीत मिली है। वहीं, दो टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही है। भारतीय टीम ने पिछले तीन श्रीलंकाई दौरों में से 2010 की सीरीज ड्रॉ रही थी, जबकि 2015 और 2017 में भारत ने मेजबानों को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। साल 2017 के दौरे पर भारतीय टीम ने श्रीलंका के सभी मैच हराये थे। अब ठीक नौ सालों के लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम के पास एक बार फिर क्लीन स्वीप कर इतिहास दोहराने का अवसर है। इस सीरीज का पहला टेस्ट गॉल में खेला जाएगा जबकि दूसरा और निर्णायक टेस्ट मैच 23 अगस्त 2024 से कोलंबो में खेला जाएगा। श्रीलंका की स्पिन को सहायता देने वाली पिच और कठिन हालातों को देखते हुए भारतीय टीम की राह आसन नहीं है। इसी कारण एक ऐसी टीम चयनित की गयी है। जिसमें अनुभवी और युवा खिलाड़ी दोनो ही शामिल रहें। टीम की बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल को शामिल किया गया है। वहीं विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत और युवा ध्रुव जुरेल को मिली है। श्रीलंकाई पिचों पर स्पिनरों की भूमिका हमेशा बेहद महत्वपूर्ण रही है, जिसे देखते हुए चयनकताओं ने रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव के अनुभवी हाथों के साथ-साथ मानव सुथार और सारांश जैन जैसे प्रतिभाशाली स्पिनरों को टीम में अवसर दिया है। वहीं, तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज संभालेंगे। यह दो मैचों की सीरीज केवल एक सामान्य द्विपक्षीय मुकाबला नहीं है, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंकतालिका में टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है।

लवप्रीत की सफलता के पीछे छिपा है परिवार का त्याग

चंडीगढ़। पंजाब के अमृतसर जिले के एक छोटे से गांव से आने वाले वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने राष्ट्रमण्डल खेलों में रजत पदक जीतकर अपनी पहचान बनायी है। लवप्रीत का यहां तक का सफर बेहद कठिन रहा है। आर्थिक तंगी और संघर्ष से निकलकर ही वह यहां तक पहुंचे हैं।

लवप्रीत एक आर्थिक रुप से कमजोर परिवार से आते हैं। उनके पिता पेशे से एक दर्जी हैं, शुरूआत से ही परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही। इतने कठिन हालातों और अभाव के बावजूद, लवप्रीत के माता-पिता ने कभी भी उन्हें खेलने से नहीं रोका।

उन्होंने उसके पदक जीतने का सपन पूरा करने कोई कसर नहीं रखी। पिता ने कभी भी लवप्रीत की ट्रेनिंग पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, भले ही इसके लिए उन्हें खुद को और भी अधिक कठिनाइयों में डालना पड़ा हो। उनकी यह दृढ़ता और बलिदान ही लवप्रीत के सफल सफर की पहली सीढ़ी बनी। परिवार के किये त्याग की भी इसमें अहम भूमिका रही।

वेटलिफ्टिंग जैसे खेल में शीर्ष पर पहुंचना केवल शारीरिक शक्ति का खेल नहीं होता, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता और अथक परिश्रम की भी

मांग करता है। लवप्रीत के लिए यह रास्ता आसान नहीं था। उन्हें अपनी डाइट, ट्रेनिंग और आवश्यक उपकरणों के लिए अक्सर संघर्ष करना पड़ा। कई बार परिवार को कर्ज का सहारा भी लेना पड़ा होगा ताकि उनके बेटे का प्रशिक्षण बाधित न हो। लवप्रीत ने हर बाधा को अपनी संकल्प शक्ति से पार किया। घंटों जिम में पसीना बहाना, सख्त अनुशासन का पालन करना और हर रोज खुद को बेहतर बनाने की ललक ने उन्हें धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर के मंच तक पहुंचाया। हर चुनौती को उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक और कदम माना।

कॉमनवेल्थ गेम्स के मंच पर, लवप्रीत का प्रदर्शन उनकी सालों की तपस्या का फल था। 176 किलोग्राम के रिकॉर्ड स्नैच और फिर क्लीन एंड जर्क में शानदार लिफ्टिंग के साथ, उन्होंने कुल 388 किलोग्राम भार उठाकर दिखा दिया कि वे किसी से कम नहीं। लवप्रीत की यह कहानी सिर्फ वेटलिफ्टिंग में एक जीत भर नहीं है, बल्कि यह उन लाखों युवाओं के लिए एक मशाल है जो आर्थिक और सामाजिक बाधाओं के कारण अपने सपनों को पूरा करने से हिचकते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर जज्बा सच्चा हो और कड़ी मेहनत करने का जुनून हो, तो वक्त को बदला जा सकता है और हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।

कारोबार

जुलाई में 2.11 लाख करोड़ रुपये पहुंचा जीएसटी संग्रह

सालाना आधार पर 15.4% की बढ़ोतरी; क्या दिखाते हैं ये आंकड़े?

नई दिल्ली। जुलाई 2026 में जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। घरेलू कारोबार और आयात से मिलने वाले कर में बढ़ोतरी से राजस्व में इजाफा हुआ है। जानिए जीएसटी संग्रह के इन आंकड़ों से क्या संकेत मिलते हैं?

जुलाई 2026 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कुल संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा। सरकार की ओर से शनिवार को जारी

मासिक जीएसटी राजस्व रिपोर्ट के अनुसार, यह जुलाई 2025 के 1.83 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 15.4 फीसदी ज्यादा है। यानी एक साल में जीएसटी संग्रह में 15.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी मजबूत घरेलू राजस्व और आयात से मिलने वाले कर में बड़ी वृद्धि के कारण हुई है।

घरेलू कारोबार से कितना बढ़ा राजस्व?

देश के अंदर होने वाले कारोबार से मिलने वाला घरेलू जीएसटी राजस्व जुलाई 2026 में 10.1 फीसदी बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया। जुलाई 2025 में यह 1.31 लाख करोड़ रुपये था।

आयात से मिलने वाले टैक्स में कितनी बढ़ोतरी हुई?

वहीं, आयात से मिलने वाले जीएसटी राजस्व में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आयात से मिलने वाला जीएसटी 28.8 फीसदी बढ़कर 66,511 करोड़ रुपये हो गया। इससे जुलाई महीने का कुल जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

क्या संकेत दे रहे हैं ये आंकड़े?

जीएसटी संग्रह के नए आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद देश में घरेलू खपत और कारोबार की गतिविधियां स्थिर बनी रहीं। घरेलू कारोबार और आयात से मिलने वाले ज्यादा कर संग्रह ने कुल राजस्व बढ़ाने में मदद की है।

जंग के बीच रियल एस्टेट को 4 महीने की राहत देने की पहल

नई दिल्ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्य रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों (रेरा) को अमेरिका-ईरान युद्ध से प्रभावित रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और निर्माण पूरा करने का समय चार माह बढ़ाने की सलाह दी है। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी परामर्श में कहा, पश्चिम एशिया तनाव से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। इससे निर्माण सामग्री की उपलब्धता में कमी आई है और रियल एस्टेट परियोजनाओं में देरी हुई है। मंत्रालय ने राज्यों के रेरा से कहा है कि जिन पंजीकृत परियोजनाओं की मूल या संशोधित या पहले से बढ़ाई गई पूर्णता अवधि 28 फरवरी 2026 या उसके बाद समाप्त हो रही है, उन्हें चार महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पश्चिम एशिया तनाव को अप्रत्याशित घटना की श्रेणी में रखा है। रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 के तहत ऐसी परिस्थितियों में पंजीकरण अवधि बढ़ाने का प्रावधान है।

भारत और भूटान ने उच्चस्तरीय वार्ता के दौरा विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान 4,000 करोड़ रुपये के रियायती ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया गया। पांचवीं भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह-अध्यक्षता विदेश सचिव विक्रम मिसरी और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लेकटुप दोरजी ने की। बैठक में भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-29) के लिए भारत की 10,000 करोड़ रुपये की सहायता के तहत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई।

कमर्शियल सिलिंडर के दाम में बड़ी कटौती

नई दिल्ली। होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में शनिवार को बड़ी कटौती की गई है। 19 किलोग्राम वाले सिलिंडर के दाम 192 रुपये घटाए गए हैं। वहीं, विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार किया गया है।

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी कीमतों के अनुसार, दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमत 2,738 रुपये होगी। पहले इसकी कीमत 2,930 रुपये थी। वहीं, एटीएफ के दाम 110 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 115 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में यह लगातार दूसरी मासिक कटौती है। इससे पहले 1 जुलाई को 183.5 रुपये की कमी की गई थी। वहीं, एटीएफ की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से 1 जुलाई को की गई कटौती

का असर खत्म हो गया है। बताया कि आज कोलकाता में 19 किलो वाले व्यावसायिक (कमर्शियल) एलपीजी सिलिंडर की कीमत में 209 रुपये और दिल्ली में 202 रुपये की कटौती की गई है। इस बदलाव के बाद, आज से कोलकाता में 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलिंडर की कीमत 2,872.50 रुपये होगी।

व्यावसायिक सिलिंडर का दाम घटने से रेस्तरां, होटल और चाय की दुकान वालों को सीधा फायदा होगा। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 19 किलो वाला व्यावसायिक सिलिंडर अब दिल्ली में अब 2,728 रुपये में मिलेगा। पहले इसका रेट 2,930 था।

क्या घरेलू रसोई गैस के दाम भी घटेंगे?

सूत्रों के मुताबिक घरेलू छढ्ढ सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बार घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उपभोक्ताओं को पहले की ही दरों पर सिलिंडर मिलेगा। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर 942 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये में मिल रहा है।

पिछली बार कब बदली थी गैस की कीमतें?

इससे पहले 1 जुलाई को भी तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की थी। इस कमी के बाद राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 2,930 रुपये हो गई थी। वहीं, कोलकाता में दाम 3,255.50 रुपये से घटकर 3,081.50 रुपये पर आ गए थे। पटना में भी 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमत घटकर 3,227 रुपये हो गई थी। यह वर्ष 2026 में व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर के दाम में दर्ज की गई पहली बड़ी कटौती थी। व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में 1 जुलाई और 1 अगस्त को हुई दोनों कटौतियां पश्चिम एशिया संकट के कारण जून में कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद की गई हैं। फरवरी के अंत में संघर्ष शुरू होने के बाद व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। 19 किलोग्राम वाले सिलिंडर का दाम 1,373 रुपये बढ़कर फरवरी के 1,740.50 रुपये से जून में 3,113.50 रुपये तक पहुंच गया था। इसके साथ ही 5 किलोग्राम वाले बाजार मूल्य वाले एलपीजी सिलिंडर की कीमत भी घटाकर 762 रुपये कर दी गई है। पहले इसकी कीमत 808.50 रुपये थी। हर महीने की पहली तारीख को बदली जाने वाली इन कीमतों का आधार अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें और विदेशी मुद्रा विनिमय दर होती हैं। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में स्थानीय कर जैसे वैट के कारण कीमतों में अंतर हो सकता है।

दावाः इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होती तो पेट्रोल 125 प्रति लीटर पहुंच जाता

नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का बचाव करते हुए कहा है कि इस प्रोग्राम ने ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा होने के दौरान पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से ग्राहकों को बचाने में मदद की। मंत्रालय के अनुसार, अगर तेल कंपनियों ने फ्यूल में इथेनॉल नहीं मिलाया होता, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच सकती थीं, जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 135 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई थी।

आरबीआईः भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 682.23 अरब डॉलर हुआ

मुम्बई। आरबीआई के अनुसार, 24 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.118 अरब डॉलर बढ़कर 682.235 अरब डॉलर हो गया। स्वर्ण भंडार और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी वृद्धि दर्ज की गई। लगातार दूसरे सप्ताह बढ़े भंडार से देश की बाहरी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने की क्षमता बढ़ी है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 24 जुलाई 2026 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 6.118 अरब डॉलर बढ़कर 682.2354 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जिससे इसके लगातार मजबूत होने का संकेत मिल रहा है। इससे पहले 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार 1.08 अरब डॉलर बढ़कर 676.237 अरब डॉलर हो गया था। लगातार दूसरे सप्ताह आई इस बढ़ोतरी से देश की बाहरी आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है। आरबीआई के अनुसार, समीक्षा अवधि में स्वर्ण भंडार (गोल्ड रिजर्व) का मूल्य 1.308 अरब डॉलर बढ़कर 103.058 अरब डॉलर हो गया। वहीं, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा माने जाने वाले विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए) 4.873 अरब डॉलर बढ़कर 555.929 अरब डॉलर पर पहुंच गईं।

ऑपरेशन हमदर्द: भोपाल रेलवे स्टेशन से 16 बच्चे सुरक्षित मिले

तीन किडनैपिंग के मामलों का भी खुलासा : 11 बालिकाएं और 5 बालक मिले

भोपाल। रेलवे स्टेशन पर बेसहारा और लावारिस बच्चों की तलाश के लिए जुलाई भर चलाए गए 'ऑपरेशन हमदर्द' में जीआरपी भोपाल को बड़ी सफलता मिली। 31 दिन के अभियान के दौरान कुल 16 बच्चों को सुरक्षित तलाशकर उनके परिजनों तक पहुंचाया गया। इनमें 3 बच्चे ऐसे थे, जिनके संबंध में अपहरण के आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि 13 बच्चे रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भटके या लावारिस हालत में मिले।

पुलिस अधीक्षक रेल अंकित जायसवाल के मार्गदर्शन में जीआरपी भोपाल ने रेलवे स्टेशन पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया।

इस दौरान बेसहारा और बेघर लोगों का सत्यापन भी किया गया। अभियान के दौरान पुलिस को एक एक माह की बच्ची (बिहार) सहित गुजरात और उत्तर प्रदेश की दो 17 वर्षीय किशोरियां मिलीं, जिनके अपहरण के मामले संबंधित राज्यों में दर्ज थे। पुलिस ने तीनों को सुरक्षित दस्तयाब कर संबंधित राज्यों की पुलिस और परिजनों को सौंप दिया।

अभियान के दौरान 13 भटके हुए बच्चे भोपाल रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और आटो से लावारिस हालत में मिले। इनमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश के नो बच्चे थे, जबकि उत्तर प्रदेश के तीन और राजस्थान के दो बच्चे शामिल रहे। वहीं सुरक्षित दस्तयाब किए गए कुल 16 बच्चों में 11 बालिकाएं और 5 बालक थे। इटारसी, नरसिंहपुर, आगर मालवा, शहडोल, चित्तौड़गढ़, लखनऊ और बस्ती सहित विभिन्न जिलों के बच्चों को पहचान और पूछताछ के बाद उनके परिजनों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। रेलवे स्टेशन पर अकेले या संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने वाले बच्चों की पहले काउंसलिंग, पहचान और सत्यापन किया जाता है। इसके बाद संबंधित पुलिस और परिजनों से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित सुपुर्द किया जाता है।

इनका कहना है

आपरेशन हमदर्द केवल भटके हुए बच्चों को परिवार तक पहुंचाने का अभियान नहीं है, बल्कि मानव तस्करी, बाल अपराध और अपहरण जैसी घटनाओं की रोकथाम का भी प्रभावी माध्यम बन रहा है। जुलाई में सामने आए इन मामलों ने रेलवे स्टेशन पर सतर्क निगरानी की अहम भूमिका को भी उजागर किया।

जहीर खान, टीआई, जीआरपी।

ग्वालियर इंटरनेशनल कॉल सेंटर फजीर्वाड़ा

ठगी के 29 बैंक खाते चिह्नित, हर दिन 50 हजार से ज्यादा के लेनदेन का खुलासा

ग्वालियर। ग्वालियर के होटल में बैठकर अमेरिकी नागरिकों को ठगने के मामले में चार आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इनके पास से जो मोबाइल, लैपटॉप मिले थे। उनकी जांच में अब तक ऐसे 29 बैंक खाते चिह्नित किए जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम के ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता था। आरोपियों के मोबाइल से मिले शुरूआती रिकार्ड के अनुसार, इन खातों के जरिए हर दिन करीब 50 हजार रुपये से अधिक का अवैध लेनदेन किया जा रहा था। यह पूरा धन अमेरिकी नागरिकों से ठगा गया। पुलिस ने जब्त किए गए सात मोबाइलों को गहन तकनीकी जांच और डिलीट डाटा की रिकवरी के लिए साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा है। पिछले सप्ताह ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे पर मोहना इलाके में स्थित होटल जैनपथ के कमरा नंबर-छह में ठगी का इंटरनेशनल कॉल सेंटर पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने चार आरोपी राजपूत अभिषेक, आर्यन राजपूत, शुभोम घोष और शिवेंद्र नरेंद्र सिंह परिहार को पकड़ा था। यह चारों गुजरात, नागालैंड और उप्र के रहने वाले हैं। यह अमेरिकी नागरिकों को लोन दिलाने का झांसा देकर फंसाते थे।

यात्रियों के लिए राहत

प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन का विस्तार, अगस्त के अंत तक लगाएगी 8 अतिरिक्त फेरे

ग्वालियर। यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रेलवे ने प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन-प्रयागराज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन अब अगस्त के अंत तक निर्धारित दिनों में अतिरिक्त फेरों के साथ संचालित होगी।

ट्रेन 8 एस्ट्रा फेरे लगाएगी

रेलवे के अनुसार, प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल (04123) को 29 जुलाई तक ही चलना था। अब इसे पांच से 30 अगस्त तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार संचालित किया जाएगा। इसी तरह,

हजरत निजामुद्दीन-प्रयागराज स्पेशल (04124) का संचालन भी छह से 31 अगस्त तक प्रत्येक गुरुवार एवं सोमवार किया जाएगा। इस दौरान ट्रेन के आठ अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। यह ट्रेन 22 कोच के साथ ही संचालित हो रही है।

रात में झांसी आती है ट्रेन

यह ट्रेन प्रयागराज स्टेशन से अपराह्न 3.25 बजे चलकर शंकरगढ़, मानिकपुर, चित्रकूट, अतर्रा, बाँदा, महोबा, कुलपहाड़, हरपालपुर, मऊरानीपुर होते हुए रात 12.50 बजे झांसी पहुंचती है।

...प्रयागराज पहुँचेगी

पांच मिनट ठहरने के बाद रात 12.55 बजे झांसी से रवाना होकर ग्वालियर, धौलपुर, आगरा, मथुरा, कोसीकला पर ठहराव लेकर सुबह 11.35 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचती है। इसी तरह, हजरत निजामुद्दीन से यह ट्रेन अपराह्न 3.45 बजे चलकर रात 12.05 बजे झांसी पहुंचेगी और सुबह 9.10 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का प्रथम जन-विश्वास दौरा 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रथम जन-विश्वास दौरे पर शुक्रवार 7 अगस्त, 2026 को छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज चिन्हित शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण की समीक्षा करेंगे। समाधान कार्यक्रम के लिये शिकायतों का चयन कर उनका प्राथमिक स्तर पर परीक्षण एवं निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। निराकृत शिकायतों के आधार पर चयनित शिकायतकर्ताओं को मुख्यमंत्री के समक्ष आमंत्रित किया जाएगा, जहाँ वे स्वयं उनसे संवाद कर समाधान की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे।

हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने देर रात जहां तलवार लहराकर फैलाई दहशत

पुलिस ने उसी सड़क पर निकाला 'अदनान बच्चा' का जुलूस

भोपाल। तलैया थाना क्षेत्र के इतवारा इलाके में देर रात एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने तलवार लहराकर इलाके में दहशत फैलाई। जिसके बाद पुलिस ने बदमाश अदनान बच्चा (19) को गिरफ्तार कर लिया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित को दबोच लिया।

उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल तलवार भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसी इलाके में आरोपित का पैदल जुलूस निकालकर लोगों को कानून का संदेश दिया। पुलिस के अनुसार गुरुवार रात करीब दो बजे अदनान

हाथ में तलवार लेकर सड़क पर घूम रहा था। वह राहगीरों को धमकाते हुए इलाके में भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था।

वीडियो सामने आते ही पुलिस सक्रिय हुई और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया। अदनान तलैया थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसका नाम पुलिस की गुंडा सूची में दर्ज है। उसके खिलाफ पहले से आठ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खिलाड़ियों और किसानों के प्रोत्साहन के निर्णयों के लिए माना आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक द्वारा युवा खिलाड़ियों और किसानों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से लिए गए निर्णय पर हर्ष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी युवाओं, किसानों, नारियों और गरीबों का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं। इसके अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। ऐसे निर्णयों का लाभ मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36 हजार 441 करोड़ रुपये के संयुक्त परिव्यय के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को बढ़ी हुई सहायता को मंजूरी दे दी है।

सड़क न होने से हाथ ठेले पर निकली बच्ची की अंतिम यात्रा

दलदल में फंसा वाहन, ग्रामीण बोले- रोड नहीं बनी तो आंदोलन करेंगे

बलपुर। जबलपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत रीमा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव में पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा न होने के कारण एक पीड़ित परिवार 11 वर्षीय मृत बच्ची के शव को 'हाथ ठेले' पर रखकर ले गया।

कीचड़ में फंसा शव वाहन, वापस लौटी गाड़ी

जानकारी के मुताबिक, ग्राम मोठार निवासी रामस्वरूप मरावी की 11 साल की बेटी माया मरावी का इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज जबलपुर में निधन हो गया था। दुखी परिजन बच्ची के शव को एक निजी वाहन से गांव लेकर आ रहे थे। लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही कच्चा रास्ता गहरे कीचड़ और दलदल में तब्दील मिला।

वाहन कीचड़ में बुरी तरह फंस गया। काफी मशक्कत के बाद जब गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई, तो उसे वापस लौटाना पड़ा। इसके बाद बेबस ग्रामीणों ने बरगी नगर से एक हाथ ठेला मंगवाया और मासूम बच्ची के पार्थिव शरीर को ठेले पर रखकर उसी कीचड़ भरे रास्ते से होते हुए गांव तक पहुंचाया।

बारिश में दलदल बन जाता है रास्ता

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव बसने के बाद से लेकर आज तक यहां एक पक्की सड़क तक नहीं बन सकी है। हर बारिश में कच्चा रास्ता दलदल बन जाता है। हालत यह है कि आपातकालीन 108 एम्बुलेंस भी गांव के भीतर आने से बचती है। मरीजों को मुख्य सड़क पर ही उतारकर चली जाती है।

आक्रोशित ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

इस अमानवीय स्थिति से क्षुब्ध होकर ग्रामीणों ने प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने तत्काल 'ऑल वेदर' (सर्व-मौसमी) पक्की सड़क बनाने की मांग की है।

उग्र आन्दोलन के लिये मजबूर होंगे

मांग करने वालों में शंकर लाल वरकड़े, लेखराम, वृंदावन वरकडे, धुरन सिंह, साजन यादव, पुन्नू लाल, पंजीलाल कुलस्ते, राजू गोंड, नर्मदा प्रसाद, रतीराम, ओम सिंह, प्रकाश मसराम, वीर सिंह परस्ते, ब्रजकिशोर, महेश यादव और रंजीत मरावी शामिल हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

कोल्ड्रिफ कफ सिरप केस : मुख्य आरोपी की पत्नी ज्योति सोनी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, 10 अगस्त से शुरू होगा ट्रायल

जबलपुर। प्रदेश के 'कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड' की सह-आरोपी ज्योति सोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।

शीर्ष अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। ज्योति सोनी इस मामले के मुख्य आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की पत्नी हैं और जिला सप्लायर के रूप में आरोपी बनाई गई हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने

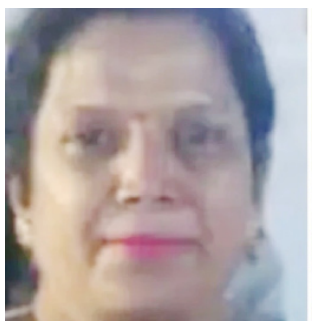

उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

ज्योति सोनी पर आरोप है कि उन्होंने मेडिकल स्टोर से निर्धारित दवा के स्थान पर जहरीला 'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' बेचा गया था। साथ ही सिरप की बोतलों के स्टॉक और रिकॉर्ड में भी कई गड़बड़ियां पाई गई थीं। इस मामले में उनके साथ अन्य 11 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था।

इन गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 में उनकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जहां से अब उन्हें जमानत मिल गई है।

10 अगस्त से गवाहों के बयान होंगे दर्ज

10 अगस्त से शुरू हो रहा ट्रायल इस केस का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। इस दौरान पुलिस और सरकारी वकील गवाहों के बयान, दवा सप्लाई के दस्तावेज और सायिंटिफिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। वहीं, आरोपियों के वकील इन साक्ष्यों और गवाहियों को चुनौती देंगे।

रिटायरमेंट से 1 दिन पहले रिश्वत लेते पकड़े गए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर

ग्वालियर। नगर निगम में गुरुवार को छह हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे को निगम ने शुक्रवार को रिटायर कर दिया। रिटायरमेंट के समय उन्हें 25 लाख का प्रोवीडेंड फंड का चेक दिया। हालांकि उनके अन्य स्वत्व रोक लिए गए हैं। साथ ही निगम के सेवानिवृति समारोह में भी सुशील कटारे को विदाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए।

अपने ही ऑफिस में पकड़े गये थे रंगे हाथ

यहां बता दें कि कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे को 31 अगस्त यानी शुक्रवार को सेवानिवृत होना था, लेकिन सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले ही ठेकेदार से भुगतान के बदले एक प्रतिशत रिश्वत को लेते हुए लोकायुक्त ने नगरनिगम कार्यालय में ही उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। सेवानिवृत्ति पर उन्हें प्रोवीडेंड फंड सहित

निगम से 60 लाख रुपये मिलना थे, लेकिन उन्हें फंड के महज 25 लाख ही दिए गए। अन्य राशि को रोक लिया गया है। बताया जाता है कि जब तक न्यायालय में मामला चलेगा तब तक उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी।

निमाड़ अंचल में जमकर बरसे बादल, खंडवा, खरगोन और बुरहानरपुर में कई जगहों पर पानी भरा

मालवा-निमाड़। अंचल में कई स्थानों पर दो दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। खरगोन जिले की गोगावां तहसील में 24 घंटे में करीब 200 और बुरहानपुर में 150 मिमी बारिश हुई। नदी-नाले उफान पर आ गए। खेतों व सड़कों पर पानी भर गया। फसलों को नुकसानी की आशंका है।

खंडवा जिले में 24 घंटे में शुक्रवार सुबह आठ बजे तक जिले में 74.4 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई। भाम राजगढ़ बांध में पानी का स्तर बढ़ने से पांच गेट खोलने पड़े। ग्राम छिरवेल में झिरन्या उद्वहन सिंचाई परियोजना के पाइप उखड़ गए। तेज हवा से इंदौर-ऐदलाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ढाबे और आदिवासी फालिया में मकानों के टिन शेड उड़ गए। राजमार्ग स्थित बिजली के खंभे भी गिर गए।

बुरहानपुर में ऊपरी क्षेत्र में हुई बारिश और परसाडोह डैम से पानी छोड़े जाने के कारण ताप्ती नदी का जलस्तर शुक्रवार शाम खतरे के निशान यानी 220.800 मीटर से ऊपर 224.100 मीटर पर पहुंच गया था। जैनाबाद पुल से करीब एक फीट नीचे पानी बह रहा था। तेज बारिश और आंधी से खकनार क्षेत्र के दो दर्जन से ज्यादा गांवों में मक्का व केला फसल खेतों में गिर गई है। खरगोन जिले के भीकनगांव क्षेत्र में खेत तालाब में तब्दील हो गए। इससे मक्का, सोयाबीन, कपास और मिर्च की खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। 24 घंटे में गोगावां तहसील में प्रदेश में सबसे अधिक करीब 200 मिमी बारिश हुई है।

खंडवा जिले में गुरुवार को तेज बारिश के बीच दो अलग-अलग स्थानों पर हुए रेस्क्यू अभियानों से सात लोगों की जान बचाई गई। इनमें चुनौतीपूर्ण अभियान हांडीकुंडी क्षेत्र

की सुक्ता नदी में रातभर चला, जहां पिकनिक मनाने गए चार युवक अचानक बढ़े जलस्तर के कारण बीच नदी के टापू पर फंस गए। करीब 10 घंटे तक चले रेस्क्यू आपरेशन के बाद शुक्रवार तड़के 4:45 बजे एसडीईआरएफ की संयुक्त टीम ने चारों को बचा लिया।

डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड आशीष कुशवाहा ने बताया कि एसडीईआरएफ ने ड्रोन के माध्यम से युवकों तक लाइफ जैकेट, भोजन और पेयजल पहुंचाया तथा पूरी रात मोबाइल पर संपर्क बनाए रखकर उनका मनोबल बढ़ाया। सुबह जलस्तर कम होते ही एसडीईआरएफ खंडवा और इंदौर की संयुक्त टीम ने रस्सियों और मोटरबोट की मदद से चारों युवकों को निकाल लिया।

अंजटी में तीन युवकों को बचाया

मोघट थाना क्षेत्र के अजंटी-चाकल्या नाले में भी गुरुवार शाम तेज बहाव के बीच पुल पर तीन युवक फंस गए थे। सूचना पर पुलिस, एसडीईआरएफ और ग्रामीणों ने संयुक्त अभियान चलाया। करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद रात लगभग 11:30 बजे तीनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

इंदौर से लौट रहे युवक बाइक सहित बहे

खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र में ग्राम गंधावड़ के समीप गुरुवार रात नाले पर बनी रपट पार करते समय बहाव तेज होने से बाइक सहित दो युवक बह गए। इनमें से 19 वर्षीय विनय वास्कले लापता है, जबकि उसका एक दोस्त तैरकर सुरक्षित निकल आया। जानकारी अनुसार दोनों युवक इंदौर कालेज में प्रवेश लेकर वापस ऊन लौट रहे थे।

पूरे वेग से बहा सिरवेल महादेव का झरना

खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश से सिरवेल महादेव का झरना पूरे वेग से बहा। मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे बालकदास महाराज ने बताया कि झरने के उफान से पास स्थित गुफा का रास्ता बंद हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल महादेव दर्शन पर रोक लगा दी गई है।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।